असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 03 मार्च, 2022 ई0
पंचम सत्र — 12 फाल्गुन,1943(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होंगे । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, पूरे बिहार में नीलगाय आतंक मचा दिया है इसके आतंक से किसान खेती करना बंद कर दिया है । पूरे बिहार में नील गाय से किसानों को मुक्ति दिलानी चाहिए । माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इसपर वक्तव्य दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । श्री अख्तरूल ईमान, प्रारंभ करें । आपलोग बैठ जाइये ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-15(श्री अख्तरूल ईमान) क्षेत्र सं0-56, अमौर

श्री अख्तरूल ईमान : पूछता हूँ सर, चूंकि ऑनलाइन हमको जवाब नहीं मिल सका है इसलिए मंत्री जी से जवाब दिलवा दें । 10.30 बजे तक ऑनलाइन में कोई आंसर नहीं मिल सका है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न सहकारिता विभाग में ट्रांसफर है ।

श्री जनक राम, मंत्री : सर, यह प्रश्न सहकारिता से वित्त विभाग में ट्रांसफर हो गया है ।

श्री अख्तरूल ईमान : सर, इसका जवाब कौन देंगे, कब दिया जायेगा ? यह किसान क्रेडिट का मामला है तो किसान क्रेडिट- किसानों को किसान क्रेडिट में कर्जा नहीं मिलता है 8 लाख की जगह पर सिर्फ 87 हजार यानी 10 परसेंट को दिया गया है और हमारे अमौर बैसा में तो 50 हजार किसानों में 5 सौ को भी नहीं दिया गया है । किसान क्रेडिट का बहुत बुरा हाल है । इसका जवाब कौन देगा, कब देगा इसको सुनिश्चित कराया जाय । रिक्वेस्ट है सर, इसको सुनिश्चित कराया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, पहले आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य यह वित्त विभाग को ट्रांसफर हुआ है जिस दिन वित्त का रहेगा उस दिन आयेगा और ट्रेजरी बेंच माननीय मंत्री जी जो जिस विभाग का ट्रांसफर होता है उसकी जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दें ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-16(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह) क्षेत्र सं0-221, नवीनगर

(श्री कुमार सर्वजीत प्राधिकृत)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । रबी 2021–22 में राज्य में यूरिया की आपूर्ति माह फरवरी, दिनांक 23.02.22 तक आवश्यकता 11,10,000 मे0ट0 के विरूद्ध 10,10,517 मे0ट0 की आपूर्ति की गयी है ।

रबी 2021–22 में माहवार आवश्यकता एवं आपूर्ति निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

(मात्रा मे0ट0 में) माह का नाम आवश्यकता आपूर्ति प्रतिशत ।

अक्टूबर -2120000018969595

नवम्बर -2123500014350861

दिसम्बर -2131500020930766

जनवरी– 22220000260739119

फरवरी-22140000207267148

कुल 1110000101051791

आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि रब्बी 2021–22 के नवम्बर एवं दिसम्बर माह में भारत सरकार द्वारा आवश्यकता से कम मात्रा में यूरिया की आपूर्ति की गयी थी । प्राप्त उर्वरकों को किसानों के बीच समुचित रूप से वितरण हेतु लगातार अनुश्रवण किया जाता रहा है तथा आवश्यकतानुसार जिलों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाता रहा है । जनवरी एवं फरवरी माह में यूरिया की आपूर्ति सामान्य है एवं राज्य के जिला में समुचित मात्रा में यूरिया उपलब्ध है ।

उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । राज्य में उच्च स्तर से लगातार उर्वरकों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार से संपर्क किया गया है तथा भविष्य में कोई कठिनाई न हो इस हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, उत्तर तो संलग्न है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा इस प्रश्न के आलोक में जो जवाब है इन्होंने माना है कि बिहार में यूरिया की घोर कमी है और इस कमी के चलते महोदय पूरे बिहार में खाद को लेने के लिए कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर किसानों को बर्बरता से पुलिस के द्वारा नहीं पीटा गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप डायरेक्ट पूरक पूछिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गया जिला में 8500 टन कम यूरिया सरकार के द्वारा जिले में दिया गया है । किसान प्रभावित हुए साथ ही मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण में जितना डिमांड था उसका 47 फीसदी मात्र माननीय मंत्री जी के द्वारा खाद की आपूर्ति की गयी । हम जानना चाहते हैं कि

आखिर कौन सी ऐसी वजह थी जिसमें पूरे बिहार में खाद की इतनी किल्लत हुई यह हमको बतावें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप को उत्तर मिला है न ? आवश्यकता के अनुसार ये आपूर्ति दिखा रहे हैं कि 91 परसेंट है । आप डायरेक्ट किसी पाटिकुलर जगह का पूछना चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी से पूछ लीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : मैंने तो पूछा कि गया जिला में 8500 टन कम यूरिया खाद की आपूर्ति की गयी । साथ ही दरभंगा, चंपारण, मुजफ्फरपुर में 47 फीसदी मात्र इनके द्वारा यूरिया की आपूर्ति की गयी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री : आपने पूरे राज्य का पूछा स्पेशफिक कोई सवाल तो आपने कोई किया नहीं है कि किस जिले में कितना आप जानना चाहते हैं । आपने तो पूरे राज्य में जो कमी दर्शाया है और उसका उत्तर राज्य के आधार पर आपको हमने उपलब्ध करा दिया है, सरकार ने उपलब्ध करा दिया है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय...

अध्यक्ष : अभी बोल रहे हैं सुन लीजिए । यह उचित नहीं है, आप सीनियर हैं बैठिए । माननीय मंत्री जी खड़े हैं बोल रहे हैं, बैठ जाइये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री : पूरे राज्य में मैं आपको बताऊं, आपने कहां के लिए पूछा है ? आपने गया के लिए पूछा है ।

श्री कुमार सर्वजीत : हमने सिर्फ गया, फिर बोलना पड़ेगा तो आप कहेंगे बैठ जाइये ।

अध्यक्ष : आप फिर बता दीजिए कहां-कहां के लिए पूछा है ?

श्री कुमार सर्वजीत : मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता के अनुसार 47 फीसदी मात्र दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और गया में 8500 टन खाद की आपूर्ति कम की गयी। यह मैं पूछ रहा हूँ ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री : यूरिया की बात आप कर रहे हैं, यूरिया में गया में अक्टूबर महीने में 5292 मे0 टन खाद रिक्वायरमेंट था और उस रिक्वायरमेंट के विरूद्ध में 4459 मे0 टन दिया यानी 125 परसेंट के और वहां खाद हमलोगों ने दिया जहां खाद जहां आपको इसकी जरूरत थी । अब आपने पूछा है पश्चिम चंपारण का..

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय..

अध्यक्ष : पूरा सुन तो लीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, क्या सुनेंगे ये सवाल किसान का है न.....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, इस तरह से थोड़े चलेगा बैठिए । सुनिए पहले मंत्री जी की पूरी बात । बैठ जाइये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री : नहीं तो कहिये तो पूरे राज्य का जिलेवार हम दे दें ।

अध्यक्ष : आप पूरे राज्य का जिलेवार दीजिएगा तो क्वेश्चन का पूरा समय ही समाप्त हो जायेगा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री : हम दे देंगे ।

अध्यक्ष : आप इनको उपलब्ध करवा दीजिए पूरे राज्य का जिलेवार ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री : महोदय, जिलावार दे देंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : ये कह हैं कि 32000 टन यूरिया का आवंटन हुआ कंपनियों के द्वारा 23472 टन मात्र गया को मिला । यही तो हम पूछ रहे हैं । ये कह रहे हैं कि हमें एक सौ की आवश्यकता थी हमने डेढ़ सौ भेज दिया । हम कह रहे हैं कि गया जिला में 32000 टन यूरिया आवंटित की गयी और कंपनियों के द्वारा हमको 23472 टन मिला और उपर से लाठी भी मिला । हम इसी का तो जवाब पूछ रहे हैं माननीय मंत्री जी से कि क्यों ऐसा हो रहा है ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पूरी जानकारी जिलावार सभी माननीय सदस्य को भेजवा देंगे । कितने खाद का रिक्वायरमेंट था, कितनी उसकी पूर्ति की गयी.....व्यवधान ।

अच्छा पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उसको सदन पटल पर रख दीजिए । अब अंतिम पूरक आपका है चलिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, सारे प्रश्न में आपको द्वारा बताया जाता है सदन को और माननीय मंत्रीगण को आप बधाई देते हैं कि उत्तर पूरा का पूरा मिला लेकिन उत्तर में कितनी सच्चाई है इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए । गया जिला में ओलावृष्टि हुआ और ओलावृष्टि में पूरे किसान का फसल चौपट हो गया और माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब क्या दिया जाता है कि फतेहपुर टनकुप्पा में फसल क्षतिग्रस्त की सूचना प्राप्त हुई जॉचोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : आप प्रश्न से हटकर मत चर्चा कीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : मैं हटकर नहीं कह रहा हूँ महोदय ।

(व्यवधान)

टर्न–2/पुलकित/03.03.2022

अल्पसूचित प्रश्न सं0– 17 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0– 83, दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : 1– उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कॉम्फेड द्वारा वर्ष 2013 में नहीं, बल्कि वर्ष 2020 में विज्ञापन संख्या– 2639,

दिनांक- 11 सितम्बर, 2020 द्वारा 142 पदों यथा लेखा सहायक, विपणन सहायक एवं पपण सहायक तथा विज्ञापन संख्या- 2769, दिनांक- 24 सितम्बर, 2020 द्वारा 39 पदों यथा कनीय तकनीशियन की नियुक्ति हेतु कुल 181 रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है ।

2- विज्ञापन संख्या- 2639, दिनांक- 11 सितम्बर, 2020 द्वारा लेखा सहायक, विपणन सहायक तथा पपण सहायक के विज्ञाप्ति 142 पदों के विरुद्ध शॉटलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची दिनांक- 25 जून, 2021 को कॉम्फेड के वेबसाईड पर अपलोड की गयी है, नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

3- कॉम्फेड के निदेशक पर्षद की दिनांक- 12 फरवरी, 2022 को सम्पन्न 100वीं बैठक में नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । कॉम्फेड द्वारा अवगत कराया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर दी जायेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है लेकिन माननीय मंत्री जी तो हैं ही नहीं, तो जवाब कौन देगा ?

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, कॉम्फेड में जो बहाली का विज्ञापन निकला था और उसका उत्तर देखिये । उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में नहीं, वर्ष 2020 में विज्ञापन निकाला गया, यह बात सही है । वर्ष 2013 में निदेशक पर्षद ने निर्णय किया और वर्ष 2020 में बहाली निकाली गयी । अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 26 जून को परिणाम जारी किया गया और आजतक इन बच्चों की नौकरी नहीं लगी । 26 जून को रिजल्ट जारी करा दिया गया, मंत्री जी ने कहा जल्द से जल्द कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं पशु पालन विभाग के निदेशक, संजय कुमार ने दिनांक- 09.07.2011 को लिखा है कि माननीय मंत्री महोदय ने गैर सरकारी प्रेषण 138, दिनांक- 07.07.2021 के माध्यम से विभाग को कहा है कि इसमें व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुई है । इसलिए इस बहाली को रोका जाय । अध्यक्ष महोदय, इसे रोके हुए 10-11 महीने हो गये हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि व्यापक पैमाने पर इसमें अनियमितता हुई और उच्चस्तरीय जांच की जा रही है । नंबर-1 इन 9 महीनों में क्या-क्या अनियमितता मिली । नंबर- 2 इसका शिकायतकर्ता कोई है, तो शिकायतकर्ता कौन था ? अनियमितता 7-8 महीने में क्या-क्या मिली ? अध्यक्ष महोदय, जो बहाली निकली

है कॉम्फेड में बहुत कमी है । मैं पहले जानना चाहता हूं कि भारी अनियमितता में या 8 महीने में क्या-क्या अनियमितता मिली ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में खंड- 3 में बोला गया है कि कॉम्फेड के निदेशक पर्षद की बैठक सम्पन्न कर ली गई है और नियुक्ति की सारी प्रक्रिया प्रारम्भ करके जो नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया है, वह जल्द पूरी कर दी जायेगी । यहां पर कोई मामला नहीं है, पूरी तरह से सरकार आश्वस्त है कि जल्द से जल्द हमलोग नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मामला है । मेरे पास निदेशक का पत्र है और मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पीत पत्र जारी किया है और विभाग से अनुरोध किया है कि इसमें भारी गड़बड़ी हैं, भारी अनियमितता है और इसको रोक दिया जाय । तब कॉम्फेड का 26 जून को परिणाम जारी हुआ, इन सभी बहालियों का । कॉम्फेड में बहुत आवश्यकता थी तो मैं यह जानना चाहता हूं महोदय, ये जो माननीय मंत्री जी का पीत पत्र के साथ संजय कुमार, निदेशक ने जो कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक को लिखा है पत्रांक/दिनांक 09.07.2021 को और इन बहालियों पर रोक का अनुरोध किया ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये, आपका पूरक क्या है ?

श्री संजय सरावगी : महोदय, मेरा पूरक यही है कि भारी अनियमितता के कारण बहाली पर रोक लगा दी गयी है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं जल्द से जल्द कर रहे हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिये । सारे जो पास हुए वे माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गये । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं फिर एक पत्र दिनांक- 12.01.2022 को निकला । इसमें यह था कि नहीं-नहीं अब इसकी बहाली की जो रोक थी उसको समाप्त कर दिया गया । अध्यक्ष महोदय, नंबर- 1 सात महीने तक क्या कारण था जो इस बहाली को रोका गया । अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या गड़बड़ी निकली ?

(व्यवधान)

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचौल' : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दोनों पत्र हैं । मैं इन पत्रों को सदन पटल पर रखना भी चाहता हूं । इसको रख दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है रखवा दीजिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, नंबर- 1 सात महीने तक बहाली की रोक लगायी गयी । पत्र को ऊपर दे दीजिये माननीय अध्यक्ष महोदय मांग रहे हैं । नंबर- 2 माननीय मंत्री जी ने कहा....

अध्यक्ष : ठीक है, इसको हम अपने स्तर से दिखवा लेंगे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, नहीं, एक मिनट दीजिये । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रोक हटा ली गयी तो मैं माननीय मंत्री जी, सरकार से पूछना चाहता हूं रिजल्ट आया हुआ है, सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है । कॉम्फेड ने लिखा है माननीय मंत्री जी ने रोक लगाई, बहुत आवश्यकता है तो क्या चलते सत्र में सात दिनों के अंदर, अध्यक्ष महोदय, परिणाम, रिजल्ट आया हुआ है । नंबर- 1 पहला तो इन सात महीनों में क्या फलाफल निकला उच्चस्तरीय जांच का और क्यों रोक लगाई गई । नंबर- 2 सात दिनों के अंदर इसी हफ्ते में क्या बहाली करके, उन लोगों को ज्वाइन कराकर क्या सदन को सूचना देंगे क्योंकि रिजल्ट वगैरह आया हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो देना है वह दिया जायेगा । सात दिन की कोई समय-सीमा न देकर हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, वे लोग जो पास किये हैं, उसमें बच्ची आकर रोने लगी मेरे पास । कहने लगी मेरी शादी रुक गई, दर्जनों की संख्या में छात्राएं आ रही हैं अध्यक्ष महोदय, जब परिणाम, रिजल्ट आ गया है तो क्यों सरकार को उन लोगों को बहाल करने में दिक्कत क्या है ? रिजल्ट आया हुआ है, अध्यक्ष महोदय, 10 महीने से रिजल्ट आया हुआ है । सातवें महीने में 26 जून को परिणाम आया । अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, चलते सदन में क्यों नहीं कर सकते । रिजल्ट आया हुआ है, अध्यक्ष महोदय तो फिर ये जो....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप इसको दिखवा लें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहेंगे । इन बच्चियों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से ...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, रिजल्ट आया हुआ है, सरकार को बहाल करने में दिक्कत क्या है ? अगर उन्होंने रोक हटा ली ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार ने कहा कि हम देख लेते हैं । आप बैठ जाइये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, रिजल्ट आया हुआ है, क्या देंखेगे ? अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है मंत्री जी बतायें कितने दिनों के अंदर कर देंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी कितने दिनों के अंदर ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की मंशा वाजिब है और मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की जायेगी और जितनी जल्दी हो सकता है, हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, समयबद्ध होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, 26 जून को रिजल्ट आ गया है, समय-सीमा बतायें ।

अध्यक्ष : आप जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत करा दीजिये, चलते सत्र में ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी है, बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष : अब विषय खत्म हो गया ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद । बढ़ने दीजिये, अब हो गया है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : सर, इसमें क्या हो रहा है । महोदय, कॉम्फेड एक सहकारी संस्था है, सहकारी फेडरेशन है और यह दूध उत्पादकों का सहकारी फेडरेशन है, महोदय। मैनेजमेंट में चुनाव के माध्यम से लोग यूनियन के अंदर जाते हैं लेकिन यूनियन का वह फेडरेशन है । उसमें दूध उत्पादन करने वाले एक भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं है । सिर्फ बिहार सरकार किसी आई0ए0एस0 ऑफिसर को वहां एम0डी0 बनाकर भेजती है । वह पूरा का पूरा एडमीनिस्ट्रेटिव बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी सिर्फ एक एम0डी0 होता है । इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें किसी नॉर्म्स को फोलो किये बिना सारे आरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर और जैसे-तैसे मनमाने ढंग से वहां अप्वाइंमेंट होता रहा है । एक समय ऐसा भी था कि उत्तर प्रदेश के शत-प्रतिशत लोगों को वहां अप्वाइंट किया गया । महोदय, इसलिए जरा इस बात पर गौर करने की जरूरत है, माननीय मंत्री जी से हम कहेंगे कि पशु पालन मंत्री और उसके नियम कायदे सहकारिता मंत्री के अंदर आते हैं । उनलोगों को कॉर्डिनेशन बनाकर उसमें एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो उसके मैंनेजमेंट को और

दूध उत्पादक जो किसान हैं, उसके जो इंट्रेस्ट हैं उसका मूल्य बढ़ाना, उसका मूल्य नियंत्रित करना, उसको लाभकारी बनाना । इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपका सुझाव ग्रहण कर लिये ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 18 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0- 122, सोनपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अस्वीकारात्मक । रबी 2021-22 में राज्य में आवश्यकता के विरुद्ध दिनांक- 25.02.2022 तक निम्न मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता रही है :-

उत्पाद	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	%
यूरिया	1110000	1020427	92
डी0ए0पी0	385000	294268	76
एन0पी0के0	190000	211269	111
एम0ओ0पी0	145000	44645	31

प्रत्येक मौसम में उर्वरकों के गुण नियंत्रण एवं अनियमित व्यापार को नियंत्रित करने हेतु जिला स्तर पर उड़नदस्ता दल द्वारा छापामारी एवं नियमित उर्वरक निरीक्षकों द्वारा प्रतिष्ठानों से नमूना (सैम्पल) लेकर गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जाता है । राज्य में वर्ष 2021-22 (दिनांक- 31.12.2021 तक) अकार्बनिक (रसायनिक खाद) 2620 नमूने विश्लेषित हुए जिसमें 72 नमूने अमानक पाये गये । कुल कार्बनिक नूमने- 69 विश्लेषित किये गये जिसमें 26 नमूने अमानक पाये गये । साथ ही जैव उर्वरक नमूने- 62 विश्लेषित किये गये, जिसमें 25 नमूने अमानक पाये गये हैं ।

अमानक पाये गए नमूनों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा की गयी है, जिसमें सभी से स्पष्टीकरण की पृच्छा एवं बिक्री की रोक लगायी गयी है । साथ ही 10 प्राथमिकी दर्ज की गयी है । सीतामढ़ी में 8 एवं 2 नवादा जिला में प्राथमिकी दर्ज की गयी है ।

12 नमूनों का पुनर्विश्लेषण हेतु भेजा गया है, जिसमें 6 नमूने पुनर्जांच के बाद मानक पाया गया है ।

अध्यक्ष : डायरेक्ट पूरक पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट पूरक पूछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में खाद की उपलब्धता की बात की है लेकिन मैं बताना चाहता हूं ।

मंत्री जी से मिलकर भी मैंने लिखकर दिया था कि हमारे जिला में मसरख में, तरैया में लोग, सोनपुर में खाद के लिए लाइन में लगकर मर गये । मंत्री जी का जवाब है – पूरे बिहार में है यही है । दूसरा मेरा जो सवाल है वह है नकली खाद, नकली खाद की आपूर्ति राज्य में हुई, उससे किसानों को जो क्षति हुई । वे कहते हैं नमूना जांच कराया, 72 में से 26 नमूने अमानक पाये गये ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : मेरा पूरक पूछना है । जो किसान लूजर रहे, जिन किसानों की फसल नहीं उगी, फसल में पौधा-फल नहीं आया तो नकली खाद की वजह से हमारे राज्य के किसान परेशान हुए और घाटे में पड़े । क्या सरकार उनको मुआवजा देगी और दोषियों को सजा देगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, दूसरा मेरा पूरक है कि माननीय मंत्री ने जिन आंकड़ों को दिया है, पूर्व के हमारे एक सदस्य ने अभी पूछा उसमें ....

अध्यक्ष : दो पूरक हो गये, तीसरा पूरक भी पूछ लीजिये एक बार ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : मैं यह कहता हूं यह उत्तर पूरा भ्रामक है और पूरे हाऊस को भ्रामक करने वाला मंत्री जी का जवाब है । मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसका सही जवाब दीजिये ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

टर्न-3/अभिनीत/03.02.2022

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रामानुज प्रसाद जी ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न राज्य स्तर का प्रश्न है और प्रश्न भी उसी पर आधारित है जो हमलोग कार्रवाइयां करते हैं और उन कार्रवाइयों में जो प्राप्त करते हैं उस पर फिर से कार्रवाई करते हैं । उसी पर उन्होंने प्रश्न कर दिया है, तो प्रश्न तो हमारी की गयी कार्रवाई पर, हमारी कृत कार्रवाई पर हुआ है । महोदय, हमने जो उत्तर दिया है बिल्कुल संतोषजनक उत्तर दिया है । रामानुज जी जो चाहते हैं वह विभाग पहले से कर रहा है । इसलिए अगर उसके लिए स्पेसिफिक हर जिले में की गयी कार्रवाई की आप बात करते हैं तो हम उसकी जानकारी भी उपलब्ध करा देंगे लेकिन इसको व्यापक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय..

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, हमने इनको उत्तर में बता दिया है कि व्यापार को नियंत्रित करने के लिए और क्वॉलिटी को नियंत्रित करने के लिए, क्वॉलिटी के

कंट्रोल के लिए हमने जितनी कार्रवाई की है उसका स्पष्ट उत्तर हमने इसमें दे दिया है और वह सबको, सारे माननीय सदस्यों को प्राप्त है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठें तो हम अगला पूरक पूछ लें । माननीय मंत्रीजी, आपने जो उत्तर दिया है वही असंतोषप्रद है और उसी उत्तर के आलोक में हमलोग फिर पूरक सवाल कर रहे हैं । आपने जो भी जवाब दिया, वो कहते हैं कि मैं यह कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं हाउस मिसलीड हो रहा है, आपको जिन पदाधिकारियों ने जवाब बनाकर भेजा है वह कहीं से न्यायोचित नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने आपके प्रश्न को गंभीरता से लिया है ।
श्री संजय सरावगी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : नहीं । अध्यक्ष महोदय, हमारा किसान जो लूजर रहा, उसके लिए मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर कौन सी योजना है, किसान की जो नकली खाद से फसल नहीं उगी और उगी तो नष्ट हो गयी उस पर आप कार्रवाई राज्य स्तर पर कर किसानों की क्षतिपूर्ति करेंगे और करेंगे तो कबतक, नहीं तो क्यों?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, क्षतिपूर्ति तो हम करते ही हैं । 530 करोड़ रुपया हमने क्षतिपूर्ति में दिया है, किसानों के खाते में सीधे गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है । बैठ जाइये अब ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, नकली खाद से किसानों को क्षति हो रही है...

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : बैठिए रामानुज जी, हम बता देते हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि 22 लाख 27 हजार 28 आवेदन आये और उसमें 13 लाख 23 हजार 615 किसानों को दिया गया । 9 लाख 3 हजार 413 आवेदन जिला में अस्वीकृत कर दिया गया । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि 9 लाख 3 हजार 413 आवेदन जो अस्वीकृत हो गये, तो क्या माननीय मंत्रीजी इसकी समीक्षा करेंगे कि 9 लाख किसान कौन थे, क्यों इनका अस्वीकृत कर दिया गया जिलों में ? यह मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ये जो 9 लाख 3 हजार 413 आवेदन अस्वीकृत किए गये उसकी समीक्षा माननीय मंत्रीजी ने किया है कि 9 लाख 3 हजार 413 आवेदन जो हैं ये अस्वीकृत क्यों हो गये ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, ये 9 लाख 3 हजार 413 आवेदन जो अस्वीकृत किये गये कुल प्राप्त आवेदनों में से, तो ये जो अस्वीकृत होते हैं वे उस आधार पर होते हैं कि कई प्रकार की गलतियां की जाती हैं । आवेदक के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी जाती और वह मशीन काउंट नहीं करती है । दूसरी बात यह है...

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मेरे सवाल का जवाब माननीय मंत्रीजी ने नहीं दिया ।

श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, मंत्री : महोदय, हम तो दे ही रहे थे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अलग से मंत्रीजी से मिलकर भी इसका जवाब ले लीजिएगा।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, हमारे जिला का...

अध्यक्ष : देखिए, समय बहुत तेजी से निकल रहा है तारांकित प्रश्न का ।

श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, मंत्री : माननीय सदस्य, आप मिल लीजिएगा, जवाब हम दे देंगे । महोदय, जो अद्यतन रसीद होती है, अद्यतन रसीद पिछले 2018-19, 2019-20 और 2020-21 इन तीनों वर्षों का हमलोगों ने मान्य किया है । अब उसके पहले की रसीद वो देंगे तो उनका आवेदन तो अस्वीकृत होगा ही होगा और इन्हीं कारणों से ये सारे आवेदन अस्वीकृत हुए हैं ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । रामानुज जी, अब बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-314 (श्री सत्यदेव राम, क्षेत्र सं0- 107, दरौली)</u>

अध्यक्ष : उत्तर आया हुआ है पूरक पूछिए ।

श्री सत्यदेव राम : जी, उत्तर आया है । महोदय, पूरक में ही आपसे आग्रह है कि आप माननीय मंत्रीजी को यह निर्देश दे दें कि वह प्रश्न और उत्तर अपने ही मुंह से पढ़ दें, एक बार सदन उससे अवगत हो जाय ।

अध्यक्ष : इसका मतलब आप उत्तर देखे नहीं हैं ।

श्री सत्यदेव राम : जी, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । आपके पी0ए0 का प्रशिक्षण भी हो गया है ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, प्रश्न भी हम ही को करना है और उत्तर भी हम ही को देना है । इन्होंने ऐसा ही कहा है ।

अध्यक्ष : आप उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : नहीं, महोदय । प्रश्न पढ़ कर फिर उसका उत्तर दें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, प्रश्न ही इनका गलत है ।

अध्यक्ष : नहीं, आप उत्तर पढ़िए इनका ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो...

अध्यक्ष : बैठ जाइये आप । बैठ जाइये ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न भी पढ़ देना जरूरी है, चूंकि प्रश्न ही इनका गलत है ।

अध्यक्ष : ठीक है । पढ़िए ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : इन्होंने कहा है...

अध्यक्ष : अब तो बैठ जाइये आप ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : क्या यह बात सही है कि राज्य में भू-लगान से छूट अधिनियम, 1970 के तहत कोसी नदी के दोनों तटबंधों के भीतर के 4 हैक्टेयर तक की जमीन से मालगुजारी (लगान) से छूट (माफ) प्राप्त है, फिर भी उन इलाकों में पदाधिकारियों व कर्मियों की मिलीभगत से लगान की वसूली की जाती है, यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

सर, इसमें मेरा कहना है, उत्तर हम पढ़ देते हैं ।

इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में नहीं है । किसी भी रैयत द्वारा इस संबंध में आपत्ति दर्ज किये जाने की सूचना नहीं है ।

विभागीय पत्रांक- 15/लेखा-10/2000 415 दिनांक- 16.06.2020 के अनुसार सेस वसूली में कोई छूट नहीं दी गयी है ।

अगर इस प्रकार का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

मेरा कहना है सर, इन्होंने जो चार हैक्टेयर, कोसी का क्षेत्र है दरभंगा से लेकर मधेपुरा तक जाती है उसमें चार हैक्टेयर का मात्र इन्होंने जिक्र किया है, जिसका इन्होंने न खाता, न खेसरा, न रकवा, न रैयत का नाम दिया है लेकिन फिर भी वह लगान अगर लिया जाता है किसान के द्वारा, तो कंप्लेन नहीं की गयी है । वैसे कोई सेस जो है, शिक्षा सेस, स्वास्थ्य सेस और रोड सेस में जो लगान लिया जाता है वह माफ नहीं है, इसको लेना है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय...

अध्यक्ष : अब तो हो गया, अब तो स्पष्ट हो गया ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इन्होंने कहा है कि कोई सूचना नहीं है लेकिन इन किसानों ने जिला समाहर्त्ता को बाजाब्ता लिखकर दिया है और उन्होंने कहा है कि, मांग में आठवें नम्बर पर देख लेंगे, तटबंध के बीच की चार हेक्टेयर तक की जमीन जिस पर लगान माफ था परंतु वसूली होती है । हमने यही कहा है कि ये अधिकारियों से

मिलीभगत करके और किसानों से वसूली की जा रही है, तो मंत्रीजी कहते हैं कि हमें कोई सूचना नहीं है, संज्ञान में नहीं है मामला, सारी रसीद और सबकुछ लागाकर जिला समाहर्त्ता को बाजाब्ते दिया गया है ।

अध्यक्ष : आप उसकी कॉपी उपलब्ध करा दीजिए । आप देख लीजिए ।
श्री विनय कुमार ।

श्री सत्यदेव राम : नहीं । महोदय, हमारा जो प्रश्न है, इन्होंने...

अध्यक्ष : यह किस जिला का मामला है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ?

श्री सत्यदेव राम : पढ़ कर सुना दे रहे हैं आपको महोदय ।

अध्यक्ष : अब जब पता ही नहीं है । आगे बढ़िए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए । श्री विनय कुमार । नहीं पूछिएगा ?
श्री पवन कुमार यादव ।

श्री विनय कुमार : नहीं सर, पूरक पूछना है ।

अध्यक्ष : आप अपना पूरक पूछिए । एक ही प्रश्न पर अटका नहीं रहेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-315 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र सं0- 225, गुरूआ)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

नगर आयुक्त, नगर निगम, गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वार्ड संख्या- 29 क्षेत्रांतर्गत मगध कॉलोनी में विगत वर्ष में नाली-गली की सात योजनाएं पूर्ण की गई हैं एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में नाली-गली की पांच योजनाएं ली गई हैं, जिसे निविदा के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु संवेदकों के साथ एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है ।

नगर निगम, गया को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त आयोग एवं षष्टम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत क्रमशः राशि रु0 5365. 38856 (तिरपन करोड़ पैंसठ लाख अड़तीस हजार आठ सौ छप्पन रुपये) मात्र तथा रु0 1940.05821 (उन्नीस करोड़ चालीस लाख पांच हजार आठ सौ इक्कीस रुपये) मात्र प्राप्त हुआ है । नगर निगम, गया को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन नगर निगम, गया द्वारा कराया जायेगा ।

पेयजल हेतु ए0डी0बी0 सम्पोषित जलापूर्ति योजनाएं बुडको के माध्यम से कार्यान्वित करायी जा रही हैं । कार्य प्रगति पर है । पूर्ण होते ही पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी ।

श्री विनय कुमार : महोदय, सर से हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा मगध कॉलोनी है, मगध कॉलोनी में माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि पांच का टेंडर करा दिए हैं जबकि उस मगध कॉलोनी में 15 रोड है महोदय, और पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं ।

-क्रमशः-

टर्न-4/हेमन्त/03.03.2022

..क्रमशः..

श्री विनय कुमार : लेकिन सोलर लाईट वगैरह का कहीं पर जिक्र नहीं है, तो वहां लाईट लगाने के लिए और जो शेष बचे हुए हैं, वहां पर रोड है, 15 मगध कॉलोनी का रोड है, शेष बचे हुए को भी कब करवाइयेगा ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इन्होंने जो नगर निगम गया के वार्ड संख्या 29 के संदर्भ में मगध कॉलोनी की सड़कों की चर्चा की है । महोदय, हम बता दें कि इसके पूर्व के वित्तीय वर्ष में 7 सड़कें बनायी गयी हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 5 सड़कों का निर्माण निर्माणाधीन है और जलापूर्ति का कार्य एशियन डवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है । अगर इसके अतिरिक्त ऐसी सड़क की कोई बात है, मैं इनको कह रहा हूं कि अगर अलग से लिखकर दे देंगे, तो हम उसे निदेशित कर देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-316 (श्री पवन कुमार यादव, क्षेत्र सं0-155, कहलगांव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अन्तर्गत प्रशस्तडीह पंचायत के प्रशस्तडीह गांव में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय स्थापित नहीं है । वर्तमान में वहां के पशुओं का इलाज प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, कहलगांव में किया जाता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री पवन कुमार यादव : प्रशस्तडीह गांव में मध्य विद्यालय, प्रशस्तडीह के ठीक सामने शंकरपुर कोठवार मौजा के खाता संख्या 2034, खेसरा नं0 378, रकबा 8 डिसमिल पर पूर्व में पशु चिकित्सालय चला करता था ।

पूर्व में प्रशस्तडीह सबौर प्रखंड का हिस्सा हुआ करता था एवं उक्त स्थान पर दशकों पूर्व मवेशी चिकित्सक की सुविधा और प्रखंड के द्वारा उक्त स्थल पर चला करता था ।

जो प्रश्न आया है सर, वह गलत प्रश्न भेजा गया है ।

अध्यक्ष : तो गलत प्रश्न क्यों भेजा आपने ?

श्री पवन कुमार यादव : हम सही भेजे हैं । जो उत्तर भेजा गया है विभाग से, वह गलत भेजा गया है । उसमें दिया हुआ है कि नहीं है वहां पर । पहले चालू था ।

अध्यक्ष : उत्तर गलत आया है ?

श्री पवन कुमार यादव : जी, उत्तर गलत आया है ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, उस जगह पर इस तरह से कोई प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय स्थापित नहीं है । अगर माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि उत्तर गलत आया है, तो इसकी जांच करा ली जायेगी और अगर सही पाया गया, तो जो भी सवाल किये हैं उन पर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्यगण, एक चीज मैं बता दूं कि पहले भी हम कह चुके हैं कि अगर आपको लगता है कि प्रश्न का जवाब गलत आया है, तो आप लिखकर दें । माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराकर आपको उसकी रिपोर्ट देंगे ।

(व्यवधान)

नहीं-नहीं ऐसा नहीं है । सकारात्मक भाव मन के अंदर रखिये ।

तारांकित प्रश्न सं0-317 (श्रीमती प्रतिमा कुमारी, क्षेत्र सं0-127, राजापाकर)

(लिखित उत्तर)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अस्वीकारात्मक है ।

राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की कोई शिकायत नहीं पायी गयी है । वर्तमान में राजापाकर विधानसभा क्षेत्र सहित वैशाली जिला में उर्वरकों की कमी नहीं है ।

राजापाकर में 34, देसरी में 11 एवं सहदेईबुजुर्ग 11 में निबंधित उर्वरक प्रतिष्ठान हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : कब तक कार्रवाई होगी ? एक ही लाइसेंस पर बहुत-सी दुकानें संचालित की जा रही हैं जिससे किसानों को खाद और बीज की समस्या उत्पन्न हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस पर कार्रवाई कब तक होगी ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, प्रश्न जो है वह यह है कि एक ही लाइसेंस के आधार पर बहुत सारी दुकानें चलायी जा रही हैं, तो इस प्रकार की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है और राजापाकर से, इस विधान सभा क्षेत्र में कोई शिकायत हम लोगों को नहीं मिली है । आपका जो यह प्रश्न है, अगर कोई शिकायत है, कोई खास लाइसेंसी की कि वह एक ही जगह से कई लाइसेंस प्राप्त करके वह दुकान चला

रहा होगा । यह जानकारी आपको होगी लेकिन एक ही लाइसेंस पर कई दुकानें नहीं चल सकती । अब प्रश्न यही है, तो ऐसा प्रश्न न होकर यह प्रश्न पूछा जा सकता था कि कई लाइसेंस लेकर और एक ही दुकान से सारे लाइसेंसी दुकान चला रहे हैं । अगर ऐसा होता तो इसका उत्तर हम लोग दे देते ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस यही कहना चाहती हूं कि पदाधिकारी सही जांच नहीं करते हैं जिसकी जानकारी माननीय मंत्री जी तक नहीं पहुंचती है, यह जानकारी मुझे है ।

अध्यक्ष : आपके पास यदि उसकी कोई पर्टिकुलर डिटेल हो तो उपलब्ध करवा दीजिए माननीय मंत्री जी को ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : जी, मैं उनको उपलब्ध कराकर कार्रवाई कराने की मांग करती हूं ।

तारांकित प्रश्न सं0-318 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र सं0-36, मधुबनी)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

मधुबनी नगर निगम के वार्ड संख्या- 09 में कुल 14 अदद चापाकल अधिष्ठापित हैं, जिसमें से 10 अदद चापाकल मरम्मति योग्य नहीं हैं एवं शेष 04 अदद चापाकल चालू अवस्था में हैं ।

वार्ड संख्या-17 में कुल चापाकलों की संख्या 18 अदद है, जिसमें से 05 अदद चापाकल मरम्मति योग्य नहीं हैं, 04 अदद चापाकल साधारण मरम्मति हेतु बंद थे, जिसे मरम्मति कर चालू कर दिया गया है एवं शेष 09 अदद चापाकल पूर्व से चालू स्थिति में हैं ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मेरा पूरक है कि माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मधुबनी के हैं कि नहीं ? दूसरा, अगर मधुबनी के हैं और उनको 02 वार्ड का हमने रेफरेंस दिया, उन्होंने रिपेयर कराया और चूंकि मधुबनी में जल-नल योजना फेलियर है, तो ऐसिड टेस्ट के आधार पर बचे हुए वार्डों का कब तक पूरा करने का प्रयास करेंगे ?

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मात्र 02 वार्ड का प्रश्न किया है, 09 और 17, तो 09 वार्ड में कुल 14 चापाकल हैं जिसमें 10 अदद चापाकल मरम्मति योग्य नहीं हैं, शेष 04 अदद चापाकल चालू हैं । 17 वार्ड में 18 अदद चापाकल हैं जिसमें 05 मरम्मति योग्य नहीं हैं और शेष चापाकल को मरम्मत करके मैंने चालू करा दिया । रही मधुबनी की बात, मैं तो मधुबनी का हूं । नहीं का

सवाल नहीं है । मधुबनी शहर में अब मेरे विभाग के जिम्मे नहीं है, यह शहरी विकास में चला गया है । इसलिए मुझसे उम्मीद नहीं करिये । जो है वह हम चालू अवस्था में रखते हैं और मैं मधुबनी का हूं और जो आपको दिक्कत होगी मैं उसको पूरा करूंगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा कि जब कराये हैं तो ऐसिड टेस्ट के तहत पूरे मधुबनी का बंद है जल नल...

अध्यक्ष : आप भी मधुबनी से हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी सर ।

अध्यक्ष : तो दोनों पड़ोसी हैं, बातचीत नहीं होती है ?

तारांकित प्रश्न सं0-319 (श्री विजय कुमार मंडल, क्षेत्र सं0-210, दिनारा)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में अधिप्राप्त धान के समतुल्य यथा संभव उसना चावल प्राप्त किये जाने का निर्णय है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में धान एवं चावल अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि निर्धारित है, जिसके पूर्व धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि तक किसानों से अधिप्राप्त धान की कुटाई कराकर चावल अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि के पूर्व शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया जाना है ।

राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के फलस्वरूप बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक निगम के द्वारा पत्र संख्या 7922, दिनांक- 09.11.2021 के द्वारा चावल मिलों को टैगिंग के संबंध में निर्गत कंडिकावार की गयी व्यवस्था तथा सहकारिता विभाग के पत्र संख्या- 9311, दिनांक- 21.12.2021 के माध्यम से किये गये अनुरोध के आलोक में उसना चावल मिलों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के पश्चात् बाध्यकारी परिस्थिति में अंतिम विकल्प के तौर पर सहकारी संगठनों के द्वारा स्थापित किये गये अरवा चावल मिलों को प्राथमिकता दिये जाने का निदेश दिया गया है ।

खंड-3 उसना मिलों की संख्या तथा क्षमता में वृद्धि होने पर उसना चावल के अनुपात में वृद्धि होगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है ।

श्री विजय कुमार मंडल : महोदय, इसमें कहना यह है कि पहले उसना चावल के मिल हमारे जिले में बहुत थे । बाद में अरवा को सरकार ने लेना शुरू किया । जब उसना मिल का चालू हुआ, तो फिर सरकार ने अरवा चावल के लिए तय कर दिया कि अरवा चावल दिया जाय, तो पहले से उसना लिया जा रहा था फिर बाद में अरवा लिया गया और जब वहां के पैक्स के लोगों ने जब उसना चावल देना शुरू किया तो अब अरवा को शुरू कर दिया गया ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर विस्तृत रूप में दिया है । माननीय सदस्य की चिंता है कि जो उसना मिल है, उसना मिलरों को ही धान दिया जाय । ये माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमारे विभाग को निर्देश दिया था कि इस बार जो धान अधिप्राप्ति होगी, उसमें उसना मिलों का उसना चावल ही लिया जायेगा । उसना मिलों को ही धान दिया जायेगा और उनसे चावल लिया जायेगा । लेकिन इस बार रोहतास जिला में उसना राईस मिलों की संख्या है, उसमें मात्र 18 उसना मिल हैं और पैक्सों का जो अरवा राईस मिल है, वह 48 है और सामान्य अरवा राईस मिल 90 हैं । यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है । चूंकि 4 जिला छोड़कर सभी जिलों में लोग उसना चावल ही पसंद करते हैं, शाहबाद ईलाका छोड़कर, तो इस बार हम लोगों ने यथासंभव प्रयास किया है और एक तिहाई इस बार उसना चावल हम लोग प्राप्त कर सकेंगे । चूंकि उसना मिलों की संख्या उतनी नहीं है । हम लोग प्रयास कर रहे हैं चूंकि उस जिले का अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी पूरे राज्य में सबसे अधिक है । 4 लाख 97 हजार मिट्रिक टन वहां लक्ष्य है और समय-सीमा निर्धारित है कि हमको कुटाई करके फिर चावल मिलेगा फिर हम पी0डी0एस0 के माध्यम से बंटवारा करेंगे । इसलिए यह हम लोगों का प्रयास ही है, लेकिन इतनी कम संख्या है मिलों की, तो यह इस बार संभव नहीं हो सकता । इसलिए विकल्प के तौर पर हम लोगों ने यह निर्देश दिया था । अगली बार से हम लोग पूर्ण रूप से उसना मिलों की संख्या भी बढ़ जायेगी, तब हम लोग उसना मिलों को धान देकर कुटाई करके उनसे चावल ले सकेंगे । इस बार थोड़ी दिक्कत है और अगली बार से जो हमारा लक्ष्य है, हम शत-प्रतिशत उसना चावल ही..

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

बड़ा सकारात्मक जवाब दिया है । बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार मंडल : अरवा जो अभी तय किया गया है । अरवा को जो तय किया गया है पैक्सों को, जानकर कुछ पैक्सों को तय किया गया है । क्यों नही सभी पैक्सों को

अरवा में तय किया जा रहा है । सीमित लोगों को तय किया गया और लोगों को छोड़ दिया गया । पारदर्शिता यह होगी कि सबको जोड़ दिया जाय ।

टर्न–5/धिरेन्द्र/03.03.2022

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो उसना राईस मिल 18 है उसको किया गया, उसके बाद पैक्स का जो अरवा राईस मिल है उसको प्राथमिकता देनी है और उसके बाद ही दूसरे अरवा मिलों को हमको प्राथमिकता देनी है चूंकि ये सहकारी समिति के पैक्सों का, इसमें सहकारिता विभाग का अरवा मिल में पूंजी लगी हुई है इसलिए उस मिल को चलाना सरकार की प्राथमिकता में है और उसके बाद यदि जरूरत पड़ेगी तो हमलोग दूसरे मिलों को भी लेंगे लेकिन अभी हमलोग इतना ही लिये हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–320 (श्री अरूण सिंह, क्षेत्र संख्या–213, काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । नासरीगंज प्रखंड के परसियां पंचायत में जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति हेतु कुल 43 आवेदकों द्वारा आवेदन दिया गया था । सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मसरूम आलम का चयन किया गया ।

वर्तमान में चयनित अभ्यर्थी मसरूम आलम, पंयायत–डिहरी के निवासी होने का मामला संज्ञान में आने एवं जाँचोपरांत सही पाये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के पत्रांक–22(मु0), दिनांक–22.02.2022 से मसरूम आलम का चयन रद्द करने हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है । जिला स्तरीय चयन समिति की अगली बैठक में मसरूम आलम के संदर्भ में नियमानुकूल निर्णय लेते हुए स्थानीय आवेदक को जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, अनुमंडलाधिकारी, बिक्रमगंज के जरिये दिनांक–22.02.2022 को अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा चयन समिति जिला को कर दिया गया है । पहला सवाल है कि कब तक मीटिंग कराई जायेगी और इसका डेट क्या होगा ? दूसरा पूरक है कि सरकार तो बड़ी जगी हुई है हमलोग सोये हुए हैं लेकिन सरकार जगी हुई है तब भी यह भ्रष्टाचार का मामला बनता है, उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार

करेंगे । 43 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जन वितरण दुकान के लिए, 42 अभ्यर्थियों को कैंसिल कर दिया गया । 43वां जो आवेदक था वह बाहरी पंचायत का था उसको कर दिया गया जबकि लाइसेंस निर्गत करने से पहले तमाम आवेदनों की जाँच होती है और तब उस पर कार्रवाई होती है तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच करायेंगे ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया है । चयन समिति की अगली बैठक में इसको रखा जायेगा और जो गलत पाया गया है, हमने विस्तार से दिया है कि वर्तमान में चयनित अभ्यर्थी मसरूम आलम, पंयायत-डिहरी के निवासी होने का मामला संज्ञान में आने एवं जाँचोपरांत सही पाये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के पत्रांक-22(मु0), दिनांक-22.02.2022 से मसरूम आलम का चयन रद्द करने हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ है । जिला स्तरीय चयन समिति की अगली बैठक में मसरूम आलम के संदर्भ में नियमानुकूल निर्णय लेते हुए स्थानीय आवेदक को जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी कब तक बैठक होगी, डेट सुनिश्चित किया जाय । दूसरी चीज जब लाइसेंस निर्गत होता है तब तमाम आवेदन की जाँच होती है । क्यों नहीं जाँच की गई ? कैसे ऐसे अनुज्ञप्ति को दे दिया गया और इसलिए यह मामला प्रकाश में आया है, भ्रष्टाचार का मामला है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस पर जाँच करवायेंगे और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि गलत किया गया, इसको हम....

अध्यक्ष : उनका पहला पूरक है कि बैठक कब तक होगी ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक महीने के अंदर इसकी बैठक कर उस पर कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : दूसरा ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लेती हूँ जिला पदाधिकारी से जाँच मंगवाकर, फिर जरूरत पड़ेगी तो वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, कहने में शर्म आता है, हमारा जो जिला है रोहतास जिला....

अध्यक्ष : चलिये, बोल दिये हैं ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । मैं एक उदाहरण इनको दे रहा हूँ कि .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको आप अपने स्तर से दिखवा लीजिये ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, इसकी जांच करा लें तो पता चल जायेगा, तमाम जन वितरण की दुकान का लाइसेंस देने में तीन-तीन लाख रुपया लिया गया है जिले के अंदर ।

श्री राजू कुमार सिंह : महोदय, यह एक जिला का मामला नहीं है, एक अनुमंडल का मामला नहीं है । अनुमंडल पदाधिकारी लगभग सारे जगहों पर, मैं अपने जिला में दो अनुमंडल को देख रहा हूँ । बड़े पैमाने पर लेन-देन कर ऐसा काम किया जाता है। इसको मंत्री संज्ञान में लें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-321 (डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, क्षेत्र संख्या-162, कटोरिया)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिला अंतर्गत कटोरिया प्रखंड के दामोदरा पंचायत वार्ड संख्या-11 में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत विभाग योजना द्वारा कार्यान्वित है, जिससे कुल-85 घरों को जलापूर्ति दी जा रही है । महेश ढुकुआ वार्ड संख्या-11 का ही एक टोला है, जो वार्ड संख्या-11 की योजना से लगभग ढाई किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है जिसमें मात्र 9 घर हैं । इस टोला में कुल 03 अदद सरकारी चापाकल चालू है, जिससे जलापूर्ति की जा रही है ।

बांका जिला अंतर्गत कटोरिया प्रखंड के बसमता पंयायत के वार्ड संख्या-13 में विभाग द्वारा योजना कार्यान्वित की गई जिससे कुल 95 घरों में जलापूर्ति की जा रही है ।

बाघा पहाड़ी ग्राम वार्ड संख्या-13 का ही भाग है, जिनके 02 टोला में क्रमशः 35 तथा 15 घर हैं एवं वार्ड संख्या-13 में अवस्थित योजना से लगभग 02 किलोमीटर की दूरी एवं 50 फीट की ऊँचाई पर अवस्थित है तथा योजना एवं बाघा पहाड़ी के बीच में नहर बहती है जिसके कारण इस ग्राम में 'हर घर नल का जल' कार्य नहीं हो पाया है । दोनों टोला में कुल 03 अदद सरकारी चापाकल चालू है, जिससे जलापूर्ति हो रही है ।

ग्राम नेमाडीह भी वार्ड संख्या-13 का ही भाग है, जो वार्ड संख्या-13 में अवस्थित योजना से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूरी एवं 50 फीट की ऊँचाई पर अवस्थित है । इस ग्राम में कुल 05 घर हैं तथा 02 अदद सरकारी चापाकल चालू अवस्था में है, जिससे जलापूर्ति हो रही है ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा जो जवाब आया है, वह पूरी तरह से असंतोषजनक है । जवाब में इन्होंने कहा है कि वहां पर आधे टोले में नल-जल

योजना का कार्य चल रहा है और आधा टोला जो है उसमें दूरी के कारण वहां पर नल-जल योजना का कार्य नहीं किया जा सकता है । दूसरी बात विभाग द्वारा आया है कि यहां पर 03 अदद चापाकल व्यवस्थित है जो कि कंप्लिटली बुरी अवस्था में है और संचालित नहीं हो रहा है । दूसरा जो इनका जवाब आया है कि बसमता पंचायत में तीन चापाकल इन्होंने कहा है कि चालू अवस्था में है, कमोबेश वहां पर भी यही स्थिति बनी हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । बांका जिला के कटोरिया प्रखंड के दामोदरा पंचायत वार्ड संख्या-11, जहां 85 घरों में जल आपूर्ति की जा रही है । महेश ढुकुआ वार्ड ....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब आपका आया हुआ है । पूरक एक बार इनको बता दीजिये ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : महोदय, पूरक इनका सुन लिये हैं, पूरक का ही जवाब दे रहे हैं । मात्र 09 घर हैं जो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है । वहां ले जाना विभाग के लिए, 2.5 किलोमीटर पर 09 परिवार हैं इसके लिए विभाग के द्वारा तीन चापाकल दिया गया है और माननीय सदस्या का कहना है कि ये तीनों चापाकल ठीक से नहीं चलता है तो हम इसको विभाग से तुरंत दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : महोदय, दूसरा वार्ड नं0-13 का है और उसमें 03 अदद चापाकल चालू की स्थिति में है, उस पर भी माननीय सदस्या कह रही हैं कि वह ठीक से नहीं चल रहा है तो उसको हम एक सप्ताह के अंदर जांच करा कर, दिखवा कर पानी को हम चालू करवा देते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-322 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के भागलपुर शहर में नगर निगम क्षेत्रांतर्गत बुडको द्वारा ए0डी0बी0 परियोजना के तहत जलापूर्ति परियोजना-1 एवं 2 हेतु पाईप बिछाने का कार्य किया जा रहा है । जलापूर्ति पाईप लाईन बिछाने के उपरांत टेस्टिंग में लगभग एक महीना का समय लग जाता है । उक्त अवधि में खोदी गई सड़क पर तत्काल मिट्टी डालकर मोटोरेबल किया जाता है । टेस्टिंग के उपरांत रोड पुनर्स्थापन का कार्य पूर्व की भांति कर दिया जाता है ।

अब तक कुल 170 कि0मी0 पाईप जलापूर्ति हेतु बिछाया गया है, जिसमें से 101 कि0मी0 रोड को पुनर्स्थापन कर दिया गया है । शेष 69 कि0मी0 रोड का पुनर्स्थापन का कार्य प्रगति पर है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को सरकार में बहुत व्यस्तता है, बहुत सारा विभाग है, इनको अधिकारियों ने गुमराह करने की कोशिश की है । जवाब सही नहीं है, एक महीना नहीं, एक-एक वर्ष से वह खोद कर, पाईप लगा कर, मट्टी डाल कर छोड़ा हुआ है, यह सच है । हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जलापूर्ति में स्मार्ट सिटी का काम स्थानीय विधायक के अनुश्रवण में कराने का आदेश निर्गत करना चाहते हैं या नहीं, तो अध्यक्ष महोदय समिति बनाकर उसकी जाँच करा लें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी ने जो प्रश्न किया है कि भागलपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत जलापूर्ति पाईप बिछाने के लिए खोदी गई सड़क, स्मार्ट सिटी के अधीन पाईपलाईन बिछाने का कार्य नहीं चल रहा है लेकिन उन्होंने अपने प्रश्न के द्वारा जिन चीजों को जानना चाहा है, ए0डी0बी0 परियोजना के तहत जलापूर्ति योजना का कार्य चल रहा है और मैंने एम0डी0, बुडको को निदेशित भी किया है क्योंकि मार्च के बाद फिर वर्षाकाल प्रारंभ हो जायेगा तो लोगों को कठिनाई होगी और जिस सड़क की पाईपलाईन का टेस्टिंग हो गया है, उसको तुरंत रिस्टोर करने के लिए निर्देश दिया है लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि मार्च माह के अंदर वैसी सारी सड़कें जिसका टेस्टिंग हो चुका है, उसका रिस्टोरेशन निश्चित तौर पर हो जायेगा । हम आपको आश्वस्त करते हैं ।

श्री अजीत शर्मा : बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मार्च तक नहीं करते हैं तो क्या उस पदाधिकारी सहित सभी पर कार्रवाई मंत्री जी करना चाहेंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम बुडको के अधिकारी को पटना से भेज रहे हैं जो दो-तीन दिनों में चले जायेंगे और सारा प्रक्रिया कर देंगे ।

अध्यक्ष : श्री विनय कुमार ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-323 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र संख्या-225, गरूआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, गया के प्रतिवेदनानुसार गया जिला अन्तर्गत 24 अंचल कार्यालय एवं 332 पंचायत हैं, जिसमें वर्तमान में 33 राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं ।

2- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । उपलब्ध राजस्व कर्मचारी से ही सभी अंचलों के विकास का कार्य तेजी से कराया जा रहा है ।

राजस्व कर्मचारी की कमी को देखते हुए राजस्व कर्मचारी के 4353 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी थी । बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इन्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 की मुख्य परीक्षा के अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कॉउंसिलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति की जायेगी ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम पूछे थे कि गया जिला में 332 पंचायत हैं, वहां पर मात्र 37 कर्मचारी हैं । इन्होंने बोला कि यह उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । चूंकि वहां 33 राजस्व कर्मचारी हैं, मतलब इनके चार और राजस्व कर्मचारी रिटायर कर गये । इन्होंने बोला कि वहां पर तेजी से काम चल रहा है । महोदय, हम पूछ रहे हैं कि जो 332 पंचायत हैं, उसमें हर पंचायत में राजस्व कर्मचारी की जरूरत है, वहां पर एक भी कर्मचारी नहीं है । हमारा परैया प्रखंड है, वह 28 तारीख से बिल्कुल खाली है । पूरे प्रखंड में एक भी कर्मचारी नहीं हैं और इन्होंने सिर्फ जवाब दिया है कि वर्ष 2014 में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है । वह अभी तक ....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये । भूमिका बनाइयेगा तो समय पार करेगा ।

श्री विनय कुमार : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं । वर्ष 2014 में इनकी बहाली की शुरूआत की गई थी जो अभी तक विचाराधीन है ।

अध्यक्ष : चलिये । श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री विनय कुमार : महोदय, यह कब बहाली होगी, मुझे पूछना है महोदय ।

अध्यक्ष : जवाब दिया गया है मंत्री जी के द्वारा । बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही । बैठ जाइये । श्री समीर कुमार महासेठ।

श्री विनय कुमार : महोदय, एक मिनट सुन लिया जाय, यह जनहित का मामला है । वहां पर बच्चों को जातीय, आवासीय और आय....

अध्यक्ष : सभी प्रश्न जनहित के हैं ।

श्री विनय कुमार : महोदय, यहां पर यह भ्रष्टाचार का मामला है । कर्मचारी नहीं रहने से वहां पर जातीय, आवासीय और आय.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बता दीजिये ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि किसी प्रखंड में अगर एक भी कर्मचारी नहीं हैं तो मैं जिला से बात कर जहां पर एक भी कर्मचारी नहीं हैं तो मैं उसकी व्यवस्था करवा दूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री समीर कुमार महासेठ ।

टर्न-6/संगीता/03.03.2022

तारांकित प्रश्न संख्या-324 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र संख्या-36, मधुबनी)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : (1) स्वीकारात्मक है ।

नगर निकाय के अंतर्गत इस प्रकार की योजना का क्रियान्वयन उस नगर निकाय के आंतरिक संसाधन एवं विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि से किया जाता है, जिसके लिए संबंधित नगर निकाय द्वारा अपने क्षेत्र के संबंधित सभी वार्डों क्षेत्रों की स्थिति को ध्यान को उपलब्ध राशि मेंरखते हुए उस निकाय के आधार पर विभिन्न योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाता है । तत्पश्चात् नगर निकाय द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं एवं राशि की उपलब्धता के अनुसार ही ऐसी योजनाओं को नगर निकाय द्वारा पारित कर क्रियान्वयन किया जाता है ।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में वर्णित योजना नगर निगम, मधुबनी के बोर्ड द्वारा चयनित है तथा प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है । चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर निगम, मधुबनी को पंचम राज्य वित्त आयोग एवं षष्टम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रमशः राशि रु0 684.19849 (छः करोड़ चौरासी लाख उन्नीस हजार आठ सौ उनचास रुपये) मात्र तथा रु0 948.91901 (नौ करोड़ अड़तालीस लाख ईकानवे हजार नौ सौ एक रुपये) मात्र प्राप्त हुआ है । नगर निगम, मधुबनी को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन नगर निगम, मधुबनी द्वारा कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : नगर आयुक्त, नगर निगम, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में वर्णित योजना नगर निगम, मधुबनी के बोर्ड द्वारा चयनित है

तथा प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है । चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर निगम, मधुबनी को पंचम राज्य वित्त आयोग एवं षष्टम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रमशः राशि रु0 684.19849 (छः करोड़ चौरासी लाख उन्नीस हजार आठ सौ उनचास रुपये) तथा रु0 948.91901 (नौ करोड़ अड़तालीस लाख ईकानवे हजार नौ सौ एक रुपये) प्राप्त हुआ है । नगर निगम, मधुबनी को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन नगर निगम, मधुबनी द्वारा कराया जायेगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : ठीक है सर, केवल यही कहना है कि हमने 3 सड़क का कहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये कब तक तीनों बनवा देंगे, बस इतना ही हम चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : नगर निगम, मधुबनी को निदेशित कर रहे हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके जल्द से जल्द कार्यान्वयन करें ।

अध्यक्ष : चलिए । श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या-325 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र संख्या-67, मनिहारी)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

समाहर्ता, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-मनिहारी, थाना नं0-333, खाता सं0-785, खेसरा सं0-623, रकबा-01 एकड़ पर वर्ष 1971 में गंगा के कटाव से विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास हेतु भूमि अर्जित की गई थी एवं कई विस्थापित परिवारों को वासगीत पर्चा निर्गत किया गया था । कालान्तर में वर्ष 2002 में मनिहारी नगर पंचायत के रूप में अधिसूचित किये जाने के कारण एवं उक्त अर्जित भूमि पर अन्य बाहरी व्यक्तियों के दखलकार होने के कारण नियमानुसार पर्चा निर्गत नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 1971 में बाढ़ से जो विस्थापित हुए थे उनमें से कुछ लोगों को अर्जित भूमि का पर्चा दिया गया है, कितने लोगों को पर्चा दिया गया है यह बात नहीं कही गई है । महोदय, उन्होंने कहा कि 2002 में मनिहारी नगर पंचायत में अधिसूचित हो जाने के कारण अब पर्चा नहीं दिया जा सकता है । महोदय यह उत्तर सही नहीं है और कदाचित सदन को गुमराह करने वाला है क्योंकि 15.04.2012 में अंचल पदाधिकारी,

मनिहारी ने इसी अर्जित भूमि पर हरिद्वार महतो व लालू महतो, पिता–स्व0 सुग्रीव महतो, नयाटोला, मनिहारी, वार्ड सं0–2, थाना–मनिहारी जिला, कटिहार को मौजा–मनिहारी थाना नं0–333, खाता नं0–785, खेसरा सं0–623, रकबा– 6 डी0 भूमि पर 6 रुपया प्रतिवर्ष की दर से लगान की दर से वासगीत पर्चा दिया गया है। यह कैसे संभव है, एक तरफ कहा जाता है कि अधिसूचित हो जाने के बाद उनको पर्चा नहीं दिया जाता है तो फिर पर्चा कैसे दिया गया ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत मामले में समाहर्ता, कटिहार के स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कटाव पीड़ित परिवारों को अर्जित किए गए जमीन में बसाकर वासगीत पर्चा दिए जाने का प्रावधान है । यद्यपि प्रश्नगत जमीन मनिहरी नगर पंचायत के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है फिर भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अर्जित किए गए भूमि पर प्रभावित परिवारों को बसाए जाने संबंधी कार्रवाई का निदेश समाहर्ता, कटिहार को दिया गया है । आपदा प्रबंधन विभाग से सहमति प्राप्त कर इसकी कार्रवाई की जायेगी । प्रश्नगत जमीन पर अगर कोई ऐसा परिवार या व्यक्ति जो कटाव से प्रभावित नहीं हुआ है तथा जबरन कब्जा करने के नियत से बस गया है, उसे दो माह के अंदर नियमानुसार अतिक्रमण वाद चलाकर बेदखल करते हुए जमीन आपदा प्रबंधन विभाग के कब्जे में ले लिये जाने का निदेश दिया गया है और जो माननीय सदस्य ने बताया है कि उसको अगर दिया गया है नियम के विरूद्ध होगा, उस पर भी कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–326 (श्री अजय कुमार, क्षेत्र संख्या–138, विभूतिपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : (1). अस्वीकारात्मक है ।

समाहर्ता, खगड़िया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, खगड़िया अंचल अन्तर्गत मौजा–जहांगीरा, खाता नं0–288, खेसरा नं0–1635, तौजी नं0–9694, थाना नं0–249, रकवा–3 डी0 प्रति दलित परिवार को पर्चा निर्गत करने हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के कार्यालय से भूमि बंदोबस्ती वाद सं0–01/2015–16 (खगड़िया अंचल) अनुशंसा के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में प्राप्त हुआ था । उक्त भूमि पर अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा चल रही जमाबंदी के रद्दीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के

आलोक में वाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण पर्चा निर्गत नहीं किया गया है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

दलित परिवार उक्त भूमि पर 20-25 वर्षों से रह रहे हैं ।

(3) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

उक्त प्रश्नगत भूमि पर पक्का मकान अवस्थित है । प्रश्नगत भूमि पर चल रही जमाबंदी के रद्दीकरण हेतु वाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में विचाराधीन है ।

(4) जमाबंदी रद्दीकरण के पश्चात् योग्य लाभुकों के बीच पर्चा वितरण की कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अजय कुमार : मेरा पहला पूरक है कि सी0ओ0 ने जांच प्रतिवेदन दिया है 2017 में, 25.05.2017 को, 25 से 30 वर्षों से गरीब लोग बसे हुए हैं, भूमिहीन हैं तो 25 से 30 साल से जो लोग बसे हुए हैं तो उनको अब तक पर्चा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इनका जो उत्तर था वह स्वीकारात्मक था और इसमें हमने जो जानकारी लिया है अपर समाहर्ता, खगड़िया द्वारा सूचित किया गया है कि अंचल खगड़िया सदर मौजा-जहांगीरा, खाता नं0-288, खेसरा नं0-1635, रकवा-2 कट्ठा 13 धुर की अवैध जमाबंदी जो क्रमशः गरीब ठाकुर, राजीव कुमार, मोहम्मद एजाजुल, मोहम्मद प्रीमी रजा के नाम से चल रहा था । मिश्रीत 3 मामले थे, मामला यह था-गरीब ठाकुर, राजीव कुमार, मोहम्मद एजाजुल, सुनवाई कर ली गई है तथा अंतिम आदेश पारित करते हुए उनके नाम से चल रहे जमाबंदियों को रद्द कर दी गई है और मोहम्मद प्रीमी रजा की जमाबंदी रद्दीकरण की अंतिम सुनवाई 03.03.2022 को निर्धारित है । सुनवाई के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अप्रैल, 2022 में जमाबंदी रद्दीकरण का अनुपालन सुनिश्चित कर दिया जाएगा और उनको पर्चा दे दिया जाएगा ।

श्री अजय कुमार : दूसरा पूरक मेरा है कि अपर समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी कैंसिल वाद चल रहा है, जब वाद चल रहा है तो दबंगों ने उस जमीन पर पक्का मकान किस अधिकारी के आदेश से उसने बना लिया, मुझे जहां तक जानकारी है लोकल जो थानाध्यक्ष है उसके मिलीभगत से वहां पर बना लिया गया है तो क्या उस थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो कहा है कि वह अवैध जमीन पर बना लिया है और मिलीभगत से बना लिया है तो मिलीभगत की कोई जानकारी देंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं जिस व्यक्ति ने बनाया है जमाबंदी रद्दीकरण के बाद, चाहे 10 मंजिला मकान हो उस पर बुलडोजर चला दिया जायेगा ।

श्री अजय कुमार : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री रणविजय साहू ।

श्री अजय कुमार : कितने दिनों में ?

अध्यक्ष : अलग से ।

श्री अजय कुमार : कितने दिनों में...

अध्यक्ष : श्री रणविजय साहू ।

तारांकित प्रश्न संख्या-327 (श्री रणविजय साहू, क्षेत्र संख्या-135, मोरवा)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : (क) नगर निगम, सीतामढ़ी द्वारा पूर्व में नागरिकों के टहलने हेतु पार्क में पी0सी0सी0 पथ का निर्माण किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-2022 में नगर निगम, सीतामढ़ी को पंचम राज्य वित्त आयोग से कुल राशि 643.62900 लाख (छह करोड़ तेतालीस लाख बासठ हजार नौ सौ रु0) एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की कुल राशि 283.20226 लाख (दो करोड़ तेरासी लाख बीस हजार दो सौ छबीस रु0) मात्र की राशि आवंटित की गई है । उक्त राशि से सड़क, नाला, पार्क एवं अन्य कार्य किया जा सकता है ।

यदि पार्क सौन्दर्यीकरण की यह योजना नगर निगम, सीतामढ़ी बोर्ड द्वारा पारित की जाती है तो बोर्ड के निर्णय के आलोक में नगर निगम, सीतामढ़ी को उपलब्ध राशि के आलोक में प्राथमिकता के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर निगम, सीतामढ़ी द्वारा विचार किया जायेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न (1) स्वीकारात्मक है, प्रश्न (2) स्वीकारात्मक है, प्रश्न (3) राज्य के सभी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु इ0इ0एस0एल0 के साथ नगर निकायों द्वारा एकरारनामा किया गया है जिसके उपरान्त इ0इ0एस0एल0 द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है । नगर परिषद् शाहपुर पटोरी और नगर

परिषद् ताजपुर सहित कुल 117 नए नगर निकायों का गठन किया गया है । इन नवगठित नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया विचाराधीन है ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि पटोरी और ताजपुर में कब तक लगवा देंगे थोड़ा आग्रह होगा कि इसकी समय सीमा बता दें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली ये सारे नगर पंचायत नवगठित हैं और इसे नए सिरे से फिर एकरारनामा करके इन सारे जो नवगठित नगर पंचायत हैं उसमें जो स्ट्रीट लाइट्स है, उसको लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे इसलिए समय सीमा तो नहीं लेकिन इतना आश्वस्त रहें कि जल्द से जल्द करवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं ।

अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी । माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 03 मार्च, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है- श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री मनोज मंजिल, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव एवं श्री रामबली सिंह यादव । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण का उपस्थापन एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर समान्य विचार विमर्श का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176 (3) और 171 (1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल लिए जाएंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, शून्यकाल का कोई जगह नहीं होता है, रात में कितने बजे से कितने बजे तक जमा किया जाय इसका कोई समय नहीं है । हम सात बजे आए देखे कि पूरा का पूरा शून्यकाल पूरा है तो सवाल है कि उसका एक स्थान निश्चित हो और एक निश्चत रूप से एक व्यक्ति को उस पर लगाया जाय और एक टाईम को निर्धारित किया जाय, जो स्थिति बना हुआ है, अब शून्यकाल पहले 20 से 25 आता था अब 100 से ज्यादा जा रहा है और किस समय कौन रखकर चला जाता है कोई पता नहीं चलता है इसका कोई आधार होना चाहिए ।

टर्न-07/सुरज/03.03.22

अध्यक्ष : शून्यकाल सदन शुरू होने के दो घंटे पहले दिया जाता है और 9 बजे से 10 बजे तक लिया जाता है, आपका जो मामला है सचिव उसको देख लेंगे ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, 5-6 बजे शाम में, 11 बजे रात को, 01 बजे रात को, कोई निर्धारित समय होना चाहिए ।

अध्यक्ष : जो पहले आएंगे उनका पहले लिया जायेगा, उस तरह का क्रम बना हुआ है उसमें कन्फ्यूजन नहीं । फिर भी एक बार दिखवा लिया जायेगा ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वैशाली जिले के जन्दाहा प्रखंड के तिसिऔता थाना अन्तर्गत शाहपुर गांव की घटना के बारे में आपको सूचना देना चाहती हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जमाने में जहां लोग चांद और तारे की बात करते हैं वहां एक गरीब महादलित की बेटी को उठाकर कुछ दबंगों द्वारा 24 दिसम्बर को ले जाया जाता है और यह कहने पर कि मेरी बेटी को वापस करो तो वे लोग कहते हैं कि दो दिन के बाद वापस कर देंगे लेकिन दो दिन के बाद उस बेटी की लाश एक तलाब में मिलती है, उसके बाद उस दलित परिवार के लोग न्याय के लिये धरना-प्रदर्शन करते हैं तो एक जाति विशेष के लोगों पर ही एफ0आई0आर0 दर्ज करके उनको प्रशासन द्वारा धमकाया जाता है कि आपलोग यदि इस तरह का धरना-प्रदर्शन करेंगे, न्याय की मांग करेंगे तो आपको जेल भेज दिया जायेगा । मैं सदन से इस केस की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती हूं ताकि उस दलित बेटी को हमलोग मरने के बाद उसको न्याय दिला सकें ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री इजहारूल हुसैन, अपना शून्यकाल पढ़ें । पढ़िये ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अन्तर्गत पोठिया प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु लगभग 70 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है, अन्यथा शिक्षा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है ।

अतः मैं पोठिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मो0 कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत गोविन्दपुर प्रखंड के पतलुका, अलीपुर, होरीलडीह एवं रोह के कर्मा गांव में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य करावें ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से भागलपुर जिला में फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में मृत जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी को कोर्ट से

निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के बजाय अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली के आधार पर अधिगृहित भूमि का मुआवजा भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत खड़हरा से मदारगंज मोड़, अमडंडा, पाठकडीह, छटपटिया होते हुए संथाल परगना (झारखंड सीमा) तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण सहित निर्माण कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय गांधी स्टेडियम जीर्णशीर्ण अवस्था में है जिस कारण कार्यक्रम के आयोजन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ।

अतः सरकार से बेगूसराय गांधी स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिला-रोहतास अन्तर्गत पटेल कॉलेज घोषिया खुर्द, बिक्रमगंज में नियमानुसार वरीय प्राध्यापक को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, दिनांक-25.02.2022 को मधुबनी जिला मुख्यालय में बस स्टैंड के पास रिश्तेदार के साथ जा रही युवती को रिक्शा से उतारकर पांच व्यक्तियों द्वारा गैंग रेप किया गया । अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

शेष एक अपराधी की गिरफ्तारी एवं विधि व्यवस्था दुरूस्त करने की मांग करता हूं ।

श्री अजित कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक सहायकों की बहाली हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विभागीय पत्रांक-910, दिनांक-02.07.2018 के आलोक में बिहार के सभी जिलों में जिला स्तरीय पैनल में प्रतीक्षारत शेष अभ्यार्थियों को पंचायतों में बहाल करने की मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल छूट गया है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिहार एवं सीवान में कमकर जाति जो इथनोग्राफिक रिपोर्ट-2011 के अन्तर्गत जनजाति में है, कमकर के नाम से जाने जाते हैं । इनका मूल जाति ''खरवार'' है ।

अतः मैं सरकार से कमकर को खरवार में सम्मिलित कर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने की मांग करता हूं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, मेरा भी शून्यकाल छूट गया है ।

अध्यक्ष : श्री सूर्यकान्त पासवान जी और श्री महा नंद सिंह जी का छूट नहीं गया है, अमान्य किया गया है ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, समहार्त्ता सीतामढ़ी रीगा अंचल के दाखिल खारिज वाद संख्या-2986/2021-2022 को ससमय निष्पादित करावें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में मुख्यमंत्री गली नली एवं नल-जल योजना के सफल संचालन हेतु चयनित वार्ड सचिवों से विगत 4 वर्षों से काम लेकर बिना मानदेय दिये हटा दिया गया है ।

राज्य सरकार से राज्य के वार्ड सचिवों को बकाया 4 वर्ष का मानदेय भुगतान करने तथा बेहतर कार्य के आधार पर समीक्षोपरांत चयन में प्राथमिकता देने की मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह जी : महोदय, मेरी सूचना क्यों अमान्य की गई ?

अध्यक्ष : श्री महा नंद सिंह जी, शून्यकाल की सूचना पूर्व में दिनांक -02.03.2022 को माननीय सदस्या श्रीमती नीतू कुमारी की शून्यकाल की सूचना के समरूप है । अतः इसलिए अमान्य किया गया है आपका ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बाजपट्टी के ग्राम-वेलहीयां में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1117(10), दिनांक-27.02.2019 द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को विधिवत चालू कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 6 हजार से अधिक किसान सलाहकार हैं जो कृषि की रीढ़ हैं । किसान सलाहकारों की स्थाई नियुक्ति हेतु मांग करती हूं ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के जजमेंट के बावजूद राज्य में 2008 से ही खाली पड़े 10 हजार से ज्यादा लाईब्रेरियन के पद पर सरकार बहाली नहीं कर रही है । लाईब्रेरियन की अविलम्ब बहाली करने की मांग करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत शिवाजीनगर प्रखंड के बल्लीपुर पंचायत के मृत बागमती नदी के पूर्वी तटबंध में शुलीस गेट का निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, स्लम बस्तियों को शहरी क्षेत्र से पुनर्वास की व्यवस्था किये बिना हटाना सरकार का गैर जिम्मेवाराना कदम है ।

मैं जनहित में मांग करता हूं कि स्लम बस्तियों को हटाने से पहले प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना के तहत सभी लोगों को घर उपलब्ध करायी जाय।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, 10 फरवरी संध्या 7 बजे दरभंगा नगर थानान्तर्गत जी0एम0 रोड पर भू-माफियाओं द्वारा पदाधिकारियों की मिलीभगत से बुलडोजर चलाकर, पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया, भू-स्वामी संजय झा, रीता झा की जलकर मौत हो गई ।

स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को मुआवजा दें ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर इशू है जिन्दा जला दिया गया, थोड़ा सरकार संज्ञान ले । राष्ट्रीय समाचार बना, बहुत गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष : सरकार इसको ग्रहण करे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दो-दो, तीन-तीन दिन बुलडोजर गया, बिना पदाधिकारियों की मिलीभगत से शहर के बीचों-बीच बुलडोजर भाग नहीं सकता मोटरसाईकिल नहीं है कि क्राइम करके चला जायेगा । उसका इतना दुस्साहस था कि हम बुलडोजर भी रखेंगे तो हम पर कुछ नहीं होगा, यह सौ परसेंट अधिकारियों की मिलीभगत से है । महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए आगे, बहुत गंभीर मामला है, मेरे घर से बगल का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण की मांग करता हूं और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग करता हूं, गंभीर कार्रवाई हो ।

टर्न-8/राहुल/03.03.2022

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, इसको ग्रहण करेंगे ।

(व्यवधान)

अब बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जब आपने आसन से कह दिया कि सरकार इसका संज्ञान ले । आसन का निदेश है सरकार जरूर इसका संज्ञान लेगी ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय जी, कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत ग्राम धड़हर में 60 वर्षों से पोखरे किनारे बसे लोगों को बेघर किया जा रहा है । सरकार तत्काल वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करावे ।

अध्यक्ष : श्री भीम कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधान सभा अन्तर्गत सैकड़ों प्राथमिक/उच्च/मध्य विद्यालयों में संपर्क पथ ना होने के चलते छात्रों को विद्यालय आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः चेनारी विधान सभा

सहित पूरे बिहार के अंतर्गत उक्त प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों में छात्रों के आवागमन हेतु संपर्क पथ निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के सासाराम शहर को नगर निगम बनने के बाद शहर में कूड़ा उठाव नहीं होने से गंदगी का अम्बार लगा रहता है जिससे आम लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है । सरकार स्थायी नगर आयुक्त को बहाल कर शहर को गंदगी से निजात दिलावे ।

श्री भरत बिन्द : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड भभुआ के जिगिनी गांव में दुर्गावती नदी पर पुल कई साल पहले से बना हुआ है । एप्रोच रोड नहीं बनने के कारण दर्जनों गांवों के लोगों को परेशानी हो रही है । सरकार से एप्रोच रोड बनाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला कृषि पर आधारित एवं बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है । यहां के किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर सयम कृषि कार्य हेतु खाद्य की आपूर्ति नहीं हो पाती है एवं खाद्य की कालाबाजारी संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर ली जाती है जिससे किसानों को काफी क्षति का सामना करना पड़ता है । अतः किसानों पर हुए अत्याचार से संबंधित विभाग के पदाधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग करती हूं ।

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलानतर्गत जहानाबाद प्रखंड के ग्राम सिलेम्पुर पटना-गया रेल लाईन के सटे बसा हुआ है । रेल के अभियंता के द्वारा सम्पर्क पथ को बराबर काट दिया जाता है जिसके चलते कई गांव के लोगों का आवागमन बंद हो गया है । सरकार से रेल लाईन के किनारे सड़क निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिलान्तर्गत अगीभुत महाविद्यालय का मुख्यमंत्री की साईट पर दर्ज नहीं है जिससे लड़कियों को 50 हजार रुपये का अनुदान नहीं मिल पा रहा है । अतः मांग करता हूं कि उस कॉलेज को जोड़ दिया जाय ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत काको प्रखंड के काजी दौलतपुर निवासी जल्फीकार अली बाबू कुंवर सिंह के प्रिय मित्र थे । 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वे भी शहीद हो गए थे । अतः नोनही-हाटी पथ का नामकरण काजी जुल्फीकार अली पथ करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय में जिलेभर से हजारों महिला-पुरूष केस से संबंधित मामलों में आते हैं मगर व्यवहार न्यायालय में एक भी शौचालय नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी व स्वच्छता प्रभावित

होती है । अतः मैं सीवान व्यवहार न्यायालय में तत्काल शौचालय निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

डॉ0 शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वी चम्पारण जिला के मो0 अब्दुल्लाह एवं वैभव कुमार के अलावा अन्य 22 छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं । राज्य सरकार शीघ्र भारत सरकार से अविलंब वार्ता कर उक्त छात्रों को भारत वापस बुलाया जाये ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिला के सभी निजी अस्पतालों सहित पूरे बिहार के निजी अस्पतालों में लिए जा रहे मनमानी परामर्श एवं जांच शुल्क पर रोक लगाने तथा परमार्श एवं जांच शुल्क आधा करते हुए एक माह तक एक परामर्श शुल्क पर ईलाज कराने की जनहित में मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के चांद सुरारी निवासी आशीष कुमार एवं पटपारा निवासी आर्यन कुमार, दोनों यूक्रेन में मेडिकल स्टूडेंट हैं । मैं सराकर से दोनों विद्यार्थियों के सकुशल वतन वापसी कराने की मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के बरबट्टा से मस्तान चौक वाया अलता जाने वाले मार्ग पर मौधो के निकट पुल निगम द्वारा पुल निर्माण कार्य अधूरा है, उसकी स्थिति काफी जर्जर है । अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि कार्य को पुनः प्रारम्भ कराकर पुल निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला में सोनमहानद कोईलवर बबुरा रोड व बिहटा पटना क्षेत्र में जहरीले कचरे के कारखाने निर्माण से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के मद्देनजर जमालपुर में राम्के कम्पनी द्वारा प्रस्तावित कचरा फैक्ट्री निर्माण पर रोक लगाने की मांग करता हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड मुख्यालय भवन अत्यंत जर्जर है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है । सरकार इसका जीर्णोद्धार करावे ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय, पालीगंज में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं होने की वजह से यहां की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । मैं सरकार से पालीगंज में रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केसरी : अध्यक्ष महोदय, भारत से नेपाल जाने वाली मालवाहक गाड़ियां जो नगर परिषद् क्षेत्र जोगबनी के आई0सी0पी0 तक जाती है । पिछले दो माह से परमान नदी पर बने लोहे का पुल क्षतिग्रस्त होने के करण लम्बी दूरी तय कर दूसरे

मार्ग से जाती हैं । एन0एच0ए0आई0 द्वारा बनाये गये नये पुल से परिचालन कराने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मियों का पैनल तैयार करने का निर्देश अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया पत्रांक–297, दिनांक–05.06.2015 को चिकित्सा पदाधिकारी खगड़िया/चौथम/मानसी/अलौली/गोगरी/परवत्ता/वैलदौर प्रखंड को दिया है । खगड़िया जिला के तहत डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मियों को चतुर्थ वर्ग पद पर समायोजना की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के परसा गांव के निकट पश्चिमी कमला नहर में स्लूईस गेट सह चेकडैम बनाकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मोतीलाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, रीगा चीनी मिल बंद हो जाने से रिजर्व क्षेत्र के गन्ना किसानों द्वारा विभिन्न चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति की गयी है । सरकार द्वारा केवल तीन चीनी मिल, सिंघवलिया चीनी मिल, गोपालगंज, हसनपुर चीनी मिल, समस्तीपुर, मझौलिया चीनी मिल, पश्चिमी चंपारण को आपूर्ति पर ही भाड़ा भुगतान की घोषणा की गई है । किसानों द्वारा अन्य चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति पर भाड़ा भुगतान की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएंगी । शेष शून्यकाल की सूचनाएं ध्यानाकर्षण सूचना के उपरांत समय बचने पर ली जाएंगी...

(व्यवधान)

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सरकार का नियम है जब तक हाउस चलेगा किसी प्रखंड में बैठक नहीं होगी लेकिन हमारे चिरैया प्रखंड में अफसर मनमानी करते हुए वहां पर 7 तारीख को पंचायत समित की बैठक रखे हुए है ऐसा कोई नियम नहीं है...

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले भी सदन में यह मामला आया है इसलिए महोदय, इसका संज्ञान लेने की जरूरत है...

(व्यवधान)

टर्न–9/मुकुल/03.03.2022

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो चिंता है, उसपर हमलोग एक निर्देश दे देते हैं कि शनिवार को इसकी बैठक रखें, क्योंकि हमलोगों को जी0पी0डी0पी0 को पूरा अपलोड करना है तो वैसी परिस्थिति में हम एक निर्देश दे

देते हैं कि इसकी बैठक जो तत्काल रोक लगाकर और शनिवार को इसको कर ले ।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य डॉ0 संजीव कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

अब बैठ जाइये ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जी संज्ञान में ले लिये हैं । माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

डॉ0 संजीव कुमार, श्री देवेश कान्त सिंह एवं अन्य अठारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, ''बिहार में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की कमी के कारण बिहार के हजारों छात्रों को एम0बी0बी0एस0 पढ़ाई के लिए निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक वर्ष नामांकन में 12,00,000/- तथा छात्रावास हेतु 3,00,000/- (कुल पंद्रह लाख रु0) खर्च करने पड़ते हैं । बिहार के गरीब मेधावी छात्र एम0बी0बी0एस0 पढ़ाई के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हजारों आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, जबकि यूक्रेन, नेपाल, चीन, फिलीपींस इत्यादि देशों में एम0बी0बी0एस0 पढ़ाई के नामांकन तथा छात्रावास में प्रत्येक वर्ष मात्र 4-5 लाख रु0 की लागत आती है, जिसके कारण बिहार के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है। बिहार के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 पढ़ाई के खर्च में Fee Capping कर 4-5 लाख रु0 प्रतिवर्ष करने तथा बिहार में और अधिक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण कर बिहार के होनहार और मेधावी छात्रों के पलायन को रोका जा सकता है ।

अत: बिहार के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 पढ़ाई के लिए Fee Capping करने तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई के नामांकन हेतु भारत सरकार की संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन0टी0ए0) द्वारा प्रत्येक वर्ष नीट (यू0जी0) परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से ही राज्य के सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन लिया जाता है । जनहित में राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में लिये जाने वाले ट्यूशन-फी का निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी0एम0ए0 पई केस में दिनांक-12.08.

2005 को पारित आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेश चन्द्रा की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र समिति द्वारा किया जाता है और एक बार तय किये गये शुल्क का पुनर्निर्धारण तीन वर्ष बाद ही किया जाता है। समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण करते समय समिति द्वारा एन0एम0सी0, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के तहत निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाता है-

(1) शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ का वेतन एवं भत्ता उस संस्थान का

(2) प्रशासनिक सेवाओं का व्यय

(3) प्रयोगशाला का संधारण लागत

(4) आकस्मिक व्यय (वैधानिक आवश्यकताओं सहित)

(5) पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं जर्नल्स की आपूर्ति का व्यय

(6) आधारभूत सुविधाओं सहित भवनों का संधारण का व्यय

(7) निवेश किये गये पूंजीगत व्यय आधारभूत सुविधाओं सहित

(8) शुल्क निर्धारण समिति द्वारा आकलित किये गये अन्य आवर्ती व्यय

यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विभिन्न देशों में एम0बी0बी0एस0 अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के मानक एवं पठन-पाठन से संबंधित आधारभूत संरचना में काफी अंतर होता है । यह भी उल्लेखनीय है कि इन देशों से उत्तीर्ण एम0बी0बी0एस0 अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के लिए अपने देश में इलाज शुरू करने हेतु योग्य चिकित्सकों की पहचान हेतु एन0एम0सी0 द्वारा फोरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा प्रतिवर्ष करायी जाती है। देश के किसी भी राज्य में प्रैक्टिस प्रारम्भ करने के पूर्व मेडिकल रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता कानूनी रूप से आवश्यक है । यह निबंधन फोरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा उर्त्तीण करने पर ही संभव है । मैं यह भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अगले अकादमिक वर्षों से देशभर के निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों हेतु यह दिशा-निर्देश/नियमन दिया है कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के 50 प्रतिशत सीटों पर छात्र-छात्राओं से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों जितनी ही फीस ली जायेगी ।

नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा नामांकन फीस संबंधी अपने दिशा-निर्देश में दिनांक-03.02.2022 को यह भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी संस्था कैपिटेशन फी किसी भी रूप में नहीं वसूल सकती है । साथ ही

एम0बी0बी0एस0/पी0जी0 कोर्स में नामांकन संबंधी फीस निर्धारण के क्रम में ''नॉट फोर प्रोफिट'' सिद्धांत के आधार पर विचार करने का निदेश दिया गया है ।

वर्तमान में बिहार राज्य में एम्स और ई0एस0आई0सी0, बिहटा समेत कुल 12 (बारह) चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी संचालित हैं तथा 12 (बारह) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माणाधीन हैं । इस प्रकार अगले 3 से 4 वर्षों में राज्य में कुल 24 (चौबीस) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल हो जायेंगे ।

माननीय सदस्यों की भावना के संबंध में एवं जनहित में शिक्षण शुल्क के उचित निर्धारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार गठित स्वतंत्र इकाई शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति को भी विभाग द्वारा सम्यक विचारण हेतु अवगत करा दिया जायेगा ।

डॉ0 संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट के पास अपना रहता है कि अपने स्टेट में क्या फीस निर्धारण किया जाता है और हर स्टेट में अलग-अलग है । अगर नेशनल मेडिकल कमीशन के हिसाब से फीस निर्धारण रहता तो पूरे भारत में यूनिफॉर्म फीस रहता । हर स्टेट में, हर कॉलेज में अलग-अलग फीस ली जाती है, यह बात माननीय मंत्री जी को भी पता होगी । मैं इनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत में बहुत ऐसे काम किये हैं, जिससे बिहार एक मार्गदर्शक के रूप में उभरा है, जैसे पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिये हैं उसके बाद अलग-अलग राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया है । उसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप इसमें भी एक कम फीस निर्धारित करें ताकि यहां से जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं वह पढ़ सकें, इससे हमारे बिहार की उन्नति होगी, वे हमारे बिहार के भविष्य हैं, यह इनके हाथ में है और ये चाहें तो हमारी सरकार यह कर सकती है, माननीय अध्यक्ष महोदय । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह काम करेंगे उसके बाद भारत के अनेक-अनेक मेडिकल कॉलेजिज जो ज्यादा फीस लेते हैं वे भी फीस कम करेंगे । इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट का देकर के इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं, कहा जाता है ''small-small changes can make a big difference in the life of talented student of Bihar" इसलिए इसपर ध्यान दिया जाय, यही मेरा आग्रह है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इसको करें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 में नामांकन, परीक्षा का आयोजन एवं अन्य सभी संबंधी दिशा-निर्देश का सीधा पर्यवेक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, इस दिशा-निर्देश का अनुपालन भारत सरकार एन0एम0सी0 एवं मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी द्वारा कराती है । मैंने अपने प्रश्न के जवाब में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही उच्च न्यायालय के माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र इकाई गठित है और उस इकाई द्वारा शुल्क निर्धारण किया जाता है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अलग-अलग कॉलेज के अलग-अलग शुक्ल होते हैं, उस संबंध में मैंने 8 जो मानक हैं उनकी चर्चा की है कि एन0एम0सी0 ने यह निर्देश दिया है कि जिस संस्थान का शुल्क तय किया जा रहा है, उन संस्थानों का शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ का वेतन एवं भत्ता देखिए, प्रशासनिक सेवाओं का व्यय देखिए, प्रयोगशाला का संधारण लागत देखिए, आकस्मिक व्यय (वैधानिक आवश्यकताओं सहित) देखिए, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं जर्नल्स की आपूर्ति का व्यय देखिए, आधारभूत सुविधाओं सहित भवनों का संधारण का व्यय देखिए, निवेश किये गये पूंजीगत व्यय आधारभूत सुविधाओं को देखिए, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा आकलित किये गये अन्य आवर्ती व्यय देखा जाता है । इसके बाद भी माननीय सदस्य की जो भावना है और मैं समझता हूं कि यह पूरे सदन की भावना होगी, मेरी भी वही भावना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही भावना है कि यह शुल्क कैसे कुछ और कम किया जाय इसीलिए मैंने कहा है कि यह सदन की जो भावना है, माननीय सदस्यों की जो भावना है उस भावना से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार गठित स्वतंत्र इकाई शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति है उसको अवगत करायेंगे और आग्रह करेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इसपर आरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए ।

अध्यक्ष : अभी बैठ जाइये । आप कहां से बोलने लगे ।

डॉ0 संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो होगा ही और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बिहार में 8 ही सरकारी मेडिकल कॉलेज थे अब 24 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, यह सरकार का बहुत बड़ा एचीवमेंट है । मेरा आग्रह है कि हरेक जिला में भी मेडिकल कॉलेज हो जाय, जैसे महाराष्ट्र में है तो वह बहुत अच्छा रहेगा । बेगूसराय और खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज की जरूरत है लेकिन

...क्रमशः...

...क्रमशः...

डॉ0 संजीव कुमार: स्वास्थ्य मंत्री बार-बार यह बोल रहे हैं कि उनका खर्च का व्यय दिखाया जा रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज का, सारा व्यय भी दिखा दिया जाय खर्च का उसके बाद भी 4 से 5 लाख से ज्यादा लेना अनुचित है । यह एक पैसा कमाने का जरिया बना दिया गया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज उसको रोकना पड़ेगा हमें बिहार के हित में, यह बहुत बड़ा मुद्दा है माननीय अध्यक्ष महोदय । इसी के लिए मैं उठाया हूं, सारे सदन के सदस्य भी हमारा...

अध्यक्ष: आपका सुझाव ग्रहण किए । श्री नीतीश मिश्रा जी ।

(व्यवधान)

वो आपके पहले हाथ उठाए हैं, बैठ जाइये आप ।

श्री नीतीश मिश्रा: माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से बताया है, मैं दो पूरक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे यहां कितने सीट्स हमारे इनटेयर कितने हैं और 12 जो हमारे प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज हैं जब बन जाएंगे तो बिहार में कितने मेडिकल सीट्स होंगे और दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि जो 12 मेडिकल कॉलेज हमारे आनेवाले समय में फंक्शनल होंगे एक कठिनाई है कि फैकल्टी की कमी हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेज में है और आज भी प्रतिनियुक्ति पर जब एम0सी0आई0 का इंस्पेक्शन होता है तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेजेज में फैकल्टी को या प्रोफेसर्स को वहां पर हमलोग प्रतिनियुक्त करते हैं । 12 प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेजेज जो हैं उनमें हमारे मेडिकल काउंसिल के जो प्रावधान हैं उसके तहत हमारे यहां सारे टीचिंग फैकल्टी हो जायं उसके बारे में सरकार की क्या योजना है ?

अध्यक्ष: इस प्रश्न से जुड़ा नहीं है फिर भी माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री: महोदय, प्रश्न से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल ही अलग प्रश्न है यह लेकिन सदन के लिए जरूरी है इसकी जानकारी रहे । अभी लगभग साढ़े अठारह सौ यू0जी0 की सीटें हैं, राज्य के अंदर में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेज हैं उसके अंदर में और भविष्य में जो मेडिकल कॉलेजेज हम खोलनेवाले हैं उन मेडिकल कॉलेजेज में भी हमको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की जरूरत है उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हम नियुक्ति करते हैं लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि फैकल्टी की कमी के कारण कठिनाइयां आती हैं और जब एम0सी0आई0 का इंस्पेक्शन होता है तो उस समय कभी-कभी डिफिसिएंसी एम0सी0आई0 की तरफ से दिखाई जाती है मैं माननीय सदस्य को इतना कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान

अचानक एक दिन में नहीं निकाला जा सकता है । यह सतत चलनेवाली प्रक्रिया है और यदि पूर्व से इस राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेजेज पर्याप्त संख्या में खोले गये होते, यदि इस राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में मेडिकल पढ़कर बच्चे आगे बढ़े होते तो आज राज्य के अंदर न चिकित्सकों की कमी होती, न चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षकों की कमी होती और मैं माननीय संजीव जी को कहना चाहूंगा कि 2005 तक 8 नहीं 6 ही सरकारी कॉलेज थे...

(व्यवधान)

सुन लीजिए, 1947 से 2005 आने में 58 साल लगे महोदय और 58 साल में 6 मेडिकल कॉलेज खुले इस राज्य में और ये 16 साल कह रहे हैं, 16 साल में 6 खोल दिए और अगले 4 साल में 12 और खोल रहे हैं, बन रहा है सब, कोई हवा में हम नहीं बोल रहे हैं, जमीन पर काम हो रहा है तो सोचिए कि 56 साल में 6 और 16, 4 साल और जोड़ दीजिए तो 20 साल में हम 18 देंगे, अब कितना काम किए सो देख लीजिए । लेकिन प्रश्न यह नहीं था प्रश्न से चूंकि अलग संबंधित प्रश्न पूछा गया पूरक तो मैंने उस संबंध में जवाब दिया है लेकिन मूल प्रश्न जो है...

(व्यवधान)

ठीक है, मूल प्रश्न जो है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य सुन लीजिए ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री: मूल प्रश्न के संबंध में मैंने कहा...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आज यूक्रेन के मामले को देखते हुए, बिहार के इतने बच्चे मेडिकल पढ़ने वहां जाते हैं, यह विषय बहुत गंभीर है कि बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ें । सरकार की सजगता दिखाई पड़ रही है लेकिन इसको और गंभीरता से लेने की जरूरत है ।

(व्यवधान)

श्रीमती शालिनी मिश्रा: इसी क्रम में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को और सदन से अनुरोध करना चाहती हूं...

अध्यक्ष: माननीय सदस्या बैठ जायं ।

श्री मनोज मंजिल: बिहार के जो बच्चे फंसे हुए हैं...

अध्यक्ष: एक मिनट, आपका सिग्नेचर इसपर नहीं है ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : महोदय, इतने बच्चे बिहार के यूक्रेन से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बिहार वापस लौटे हैं, मनोज मंजिल जी किसी दिन एक फूल लेकर नहीं गए किसी लड़के का स्वागत करने के लिए और यहां भाषण दे रहे हैं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री लखेन्द्र कुमार जी ।

(व्यवधान)

मंजिल जी, बैठ जाइये, गंभीरता से सुनिये ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को, यूक्रेन में फंसे हुए बिहार और देश के बच्चे को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाए, हमारे वैशाली जिला में पांच बच्चे, उसी से जुड़ा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: भूमिका में इतना समय बर्बाद मत करिये ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन: पांच बच्चे यूक्रेन से आए हैं, हम परिवार के लोगों से मिले और परिवार के लोगों से मिलने के बाद, उनमें मैक्सिमम विद्यार्थी मेडिकल के छात्र थे । मेडिकल के छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं । हमने पूछा आप यूक्रेन क्यों गए तो कहा कि वहां फीस बहुत कम लगता है और दूसरा क्या है आरक्षण का कैटगरी भी वहां तय किया गया है, आरक्षण के आधार पर, मैं केवल माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए क्या इसमें आरक्षण रोस्टर पर भी ध्यान दिया गया है क्या ? इसमें खर्च भी निर्धारित की गई है क्या ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष: यह इस प्रश्न से...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: महोदय, जो बार-बार इसपर चर्चा हो रही है, यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तो पूरी केंद्र सरकार लगी हुई है, वहां से जो आते हैं वे लोग घर पहुंचाये जा रहे हैं लेकिन यह बात तो अभी नोटिस में आया है कि सब जगह के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए वहां इतने लोग जा रहे हैं । यह किसी को मालूम था ? हमलोगों को तो मालूम नहीं था कि इतना मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए अपने राज्य और देश को छोड़कर के कोई विदेश में जा रहा है और अभी बात आ रही है कि वहां पर पैसा कम लग रहा है, पैसा कम लग रहा है तो यह तो नेशनल लेवल पर न सोचना पड़ेगा । यहां पर जो भी एडमिशन होता है उसके लिए तो पूरा कंपीटीशन देशभर में न होता है, नेशनल लेवल पर होता है । अगर सरकारी में, सुन लीजिए पहले...

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब सुनिये पहले ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः बात को सुन लीजिए, जब यहां पर जो भी कंपीटीशन होता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो सब जगह के लिए उसी से एडमिशन होता है । अब बाहर जा रहा है जिसको कोई परीक्षा तो देनी नहीं है तो वहां गया है तो अब न सारी बात आ रही है कि यहां के बजाय बाहर इतने लोग जा रहे हैं तो इस सब चीज पर एक बार गौर से नेशनल लेवल पर सोचना है। गौर करियेगा कि बिहार एक गरीब राज्य है, सिर्फ यहां के लोग नहीं गए हैं, अमीर-अमीर राज्य के लोग भी गए हैं वहां पढ़ने के लिए तो यह समझ लीजिए न कि कोई एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह का प्रॉब्लम है, यह तो राष्ट्रीय स्तर पर ही सोचा जाएगा कि हमारे राज्य के बच्चे यहां के बजाय दूसरे देशों में मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या उनको ये सुविधा इतनी ज्यादा है तो यहां क्या किया जा सकता है कि किसी को बाहर जाने की जरूरत न हो । अब यह तो एक अलग बात है लेकिन यह बात जो आप कह रहे हैं न यह तो हमलोगों को भी पहली बार जानने को मिली है कि इतने लोग बाहर पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं जबकि बिहार, इस देश में भी है और यहां भी, सरकारी भी, प्राइवेट भी सब बात कर रहे हैं हमलोग तो कोशिश कर ही रहे हैं लेकिन एक नयी चीज आ गई है, यह बात सही है यह तो देखना पड़ेगा ही और हमलोगों को तो आश्चर्य लग रहा है कि यहां से भी साधारण इलाके के लोग, परिवार के लोग इतना ज्यादा विदेश में भेज दे रहे हैं, कैसे इतनी जानकारी है, यह नया-नया सोशल मीडिया जो आ गया है उसी से इन सब चीज की जानकारी है, हम तो सोशल मीडिया के पहले वाले हैं।

(व्यवधान)

इतना ज्यादा नहीं जाते थे । देखिए अब यूक्रेन कहां था...

(व्यवधान)

एक बात और, यूक्रेन तो रूस का ही न हिस्सा था, तो वहां जो जाते थे रूस में वह तो कम्युनिस्ट जाते थे न । पहले भी जाते थे तो यूक्रेन तो रूस का ही हिस्सा था तो उस समय तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वाले जाते थे । सी0पी0आई0 और सी0पी0एम0 के लोग ही बाहर पढ़ने जाते थे । पुरानी बात जरा जान लीजिए, अब नयी बात आई है । आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही थे, उसी का एक हिस्सा हो गए न । मेरा कोई विरोध नहीं है, आप बात समझिए । हमलोग भी, आपको हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमलोगों को तो बहुत हाल में यह बात जानने को मिली है कि इतने लोग बाहर चले जा रहे हैं तो

सचमुच सोचना पड़ेगा कि किसी को, पहले तो हमलोग वही जानते थे कि कुछ ही लोग जा रहे थे लेकिन अब इतने लोग जा रहे हैं तो इन सब चीजों पर तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, ये विचार चल रहा है और करेंगे लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी अचानक कोई राज्य सरकार का ही सिर्फ विषय नहीं है यह तो सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे बच्चे-बच्चियों को बाहर जाने की कोई नौबत न आए यह हमलोग जरूर सोचना चाहेंगे, यह जरूर है यह बात भी मन में रखिए ।

टर्न-11/अंजली/03.03.2022

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है, मेरा नाम भी है इसमें ।

अध्यक्ष : आपका नहीं है, बैठ जाइए आप । आप बोलिये ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसकी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे राज्य से किन-किन देशों में छात्र पढ़ने जा रहे हैं ? एक छोटे से 4 करोड़ की आबादी वाले देश में इतने लोग जाते हैं तो देश भर में कितने जाते होंगे, तो कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था कमजोर है ।

अध्यक्ष : आप बैठिये । कुंदन जी आप बोलिये ।

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अगले 4 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और आज भी और कल भी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उस 12 में से एक बेगूसराय भी है तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जब मैंने पिछली बार भी सदन में पूछा कि बेगूसराय में जमीन आवंटित हो गया है मेडिकल कॉलेज के लिए, कई साल हो गए, इन्होंने कहा कि एक अड़चन है कि कोर्ट में केस है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है उस अड़चन को दूर करने के लिए और किस बयान पर यह कह रही है कि अगले चार साल में बेगूसराय में...

अध्यक्ष : आप अलग से प्रश्न ले आइए, इस प्रश्न से हट कर है । जिस विषय पर है ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, इसमें है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोला जाय, उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि 12 खोले जायेंगे उसी में है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने साफ कहा है कि सरकारी कॉलेज के साथ-साथ निजी कॉलेज को भी प्राथमिकता सरकार दे रही है ।

माननीय सदस्य, श्री अवध विहारी चौधरी जी, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री अवध विहारी चौधरी, भूदेव चौधरी एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत सिवान के हसुआ-बंकामोड़-शाहपुर जाने वाली सड़क लगभग 18 किलोमीटर लंबी है । यह सड़क सिवान और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है । सिवान से बदली हसुआ तक 9 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत है एवं बदली हसुआ से बंकामोड़-शाहपुर होकर प्रतापपुर झरही नदी तक लगभग 9 किलोमीटर सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क की स्थिति अच्छी नहीं रहने एवं उसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण नहीं होने के कारण छोटे-बड़े वाहनों को उत्तर प्रदेश की सीमा से हसुआ बदली होते हुये स्पिनिंग मिल से सिवान तक आने में कठिनाई होती है । जिसके कारण सिवान जिला के गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित प्रतापपुर चीनी मिल में गन्ना ले जाने में दिक्कत होती है ।

अतः सिवान हसुआ बदली से बंकामोड़ होकर शाहपुर-प्रतापपुर चीनी मिल तक ग्रामीण कार्य विभाग के 9 किलोमीटर सड़क को पथ निर्माण विभाग में लेकर पथ निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण का दिया हुआ जो सवाल है, दो विभाग से संबंधित है, इसलिए थोड़ा समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : माननीय मंत्री जी ने क्या जवाब दिया ?

अध्यक्ष : समय चाहिए । माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

श्री दामोदर रावत, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का गृह विभाग से संबंधित 302वां प्रतिवेदन, पथ निर्माण विभाग से संबंधित 313वां प्रतिवेदन एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित 314वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : अब शेष शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्री मो0 अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र बहादुरगंज, टेदागाछ में लक्ष्य के अनुरूप यूरिया एवं खाद नहीं मिलने के कारण कृषको को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।

मैं माननीय कृषि मंत्री से मांग करता हूं कि ससमय लक्ष्य के अनुरूप यूरिया एवं खाद मुहैया कराने की कृपा की जाय ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार के समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग, दरभंगा और समस्तीपुर में भू-माफियाओं के आतंक, वैशाली में महिला उत्पीड़न और गया बेलागंज में बालू माफियाओं के द्वारा पुलिस प्रशासन को कठपुतली बनाये जाने की घटनाओं के राजनीति संरक्षण की जांच हो ।

श्री गोपाल रवि दास : अध्यक्ष महोदय, बैरिया (पटना) बस स्टैंड से एम्स पटना तक बस परिचालन शुरू करने की मांग करता हूं ।

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत कोटवा प्रखंड के अहिरौलिया पंचायत में अवस्थित अहिरौलिया कबीर पंथी मठ का चहारदीवारी निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य कराने की मांग करता हूं ।

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सालय बहेड़ी जिला दरभंगा से दिनांक-31.01.2010 को अवकाश प्राप्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारी श्री जलेश्वर यादव, ग्राम-कुशियाम (बहेड़ी) जिला-दरभंगा को संशोधित वेतनमान देने की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के बाबा गिरवरनाथ पर्वत को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय तथा शाहकुंड बाजार को जाम से मुक्त कराया जाय ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत सभी प्रखंडों में आधार केंद्रों का सुचारू रूप से चालू रहने रहने के कारण आम जनता को आधार कार्ड बनाने और सुधार कराने में काफी कठिनाई होती है, जिन कठिनाईयों को दूर करने के लिए पंचायतवार आधार केंद्र का होना आवश्यक है । जिसे शीघ्र से शीघ्र चालू करवाने की कृपा की जाय ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, यास तूफान के कारण शेखपुरा जिला के किसानों को भारी मात्रा में फसलों की क्षति हुई है सदन के माध्यम से किसानों के हित में फसल क्षति मुआवजा शीघ्र देने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित राज्य के विश्वविद्यालय से संबद्ध 250 से ज्यादा कॉलेज को शिक्षण कार्य हेतु अनुदान मिलता है परंतु आधारभूत संरचना विकास हेतु अनुदान की व्यवस्था नहीं है जिससे छात्रों को काफी कठिनाई होती है ।

अतः मैं सरकार से संबद्ध कॉलेज में आधारभूत संरचना विकास हेतु अनुदान देने की मांग करता हूं ।

श्री रामवृक्ष सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड ग्राम-रौन, निवासी श्री अंकित राज, पिता अरूण कुमार सहित सभी भारतीय छात्र को यूक्रेन से सुरक्षित भारत वापसी हेतु केंद्र सरकार से प्रस्ताव भेजने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अंतर्गत कुशमौल पंचायत के चौपाल टोला सिति बजरंगबली स्थान से जयनगर घूरणा मुख्य पक्की सड़क तक जानेवाली सेड में जे0बी0सी0 नहर पर पुल निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखंड के ग्राम कुर्मा से फत्तूचक गांव तक लगभग दो किलोमीटर सड़क काफी जर्जर हो गई है । लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । बरसात के दिनों में एक गांव से दूसरे गांव का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है । अतएव अतिशीघ्र सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि गया जिला के परैया प्रखंड के ग्राम-सखबां में पुराने तालाब की सफाई एवं सौंदर्यीकरण का कार्य शीघ्र कराया जाय ।

अध्यक्ष : श्री सुनील मणि तिवारी । नहीं हैं ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के ग्राम पंचायत बैरियाडीह धवही लोहार टोला शिव मंदिर से भाया देवेन्द्र सहनी के घर होते हुए जमुनिया बाजार तक सड़क आजादी के बाद आज तक बना ही नहीं है, जो चार पंचायतों को जोड़ती है ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि सड़क का निर्माण करावें ।

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला में पैक्स के माध्यम से 2021-2022 में लक्षित 45 हजार मे0 टन धान खरीद के बावजूद जिला समेत मोरवा विधान सभा के कई पंचायतों में सभी किसानों का धान खरीद नहीं हो सका है । धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख मे0 टन करने की मांग करता हूं ।

श्री मो0 इसराइल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के मुस्तफापुर एवं मिठनसराय टेनि बांध का निर्माण अतिशीघ्र कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मो0 नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रफीगंज के पंचायत बघौरा के ग्राम गमहरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाय ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर नगर परिषद के वार्ड नं0-07 में स्थित खाता संख्या-266, खेसरा संख्या-202, रकवा-86 डी. में फैला तालाब 35 वर्षो से अतिक्रमण युक्त एवं जर्जर है । अतएव उक्त तालाब का जीर्णोद्धार करावें ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत पाठारी जमीन के सिंचाई के लिये पंप से डिस्चार्ज के अनुरूप सरकार द्वारा तय विद्युत आपूर्ति के समय में वृद्धि की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती संगीता कुमारी : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के मोहनियां में अवस्थित महाराणा प्रताप कॉलेज में प्रावधान से ज्यादा शुल्क छात्र/छात्राओं से वसूल किया जा रहा है और प्राप्त शुल्क वित्तीय अनियमितता की जा रही है । शुल्क एवं वित्तीय अनियमितता की जांच करावें ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत करगहर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी सह दवा व्यवसायी श्री उमाशंकर शर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार शर्मा यूक्रेन के खारकीव शहर में एम0बी0ब0एस0 की पढ़ाई कर रहे हैं तथा अभी युद्ध की स्थिति में वहां के किसी बंकर में शरण लिये हुये हैं । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उचित माध्यम से संपर्क कर उनके सकुशल वापसी को सुनिश्चित करें ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा बेल बराही पथ ओबरा एन. एच.-139 से पूर्व बाजार भाग तक 500 मीटर सड़क निर्माण हेतु संवेदक को पथ निर्माण विभाग औरंगाबाद प्रमंडल कार्यपालक अभियंता द्वारा समय अवधि नहीं दिये जाने से सड़क निर्माण कार्य अधूरा है । संवेदक को समय अवधि दिया जाय ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के डोभी प्रखंड के खरांटी पंचायत के पैतला ग्राम में प्राथमिक विद्यालय विगत 16-17 वर्षों से भवन नहीं रहने के कारण मध्य विद्यालय खसंटी में संचालित हो रही है जिससे बच्चों के पठन-पाठन में काफी परेशानी होती है ।

अतः उक्त गांव में विद्यालय का निर्माण कराने का कष्ट करें ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नरकटियागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को रेफरल अस्पताल में अपग्रेड करने की मैं सदन से मांग करती हूं ।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के ग्राम-तिलन बिगहा स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-13/मधुप/03.03.2022

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण का उपस्थापन

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2021-22 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा । इसके लिए दिनांक- 03 एवं 04 मार्च, 2022 की तिथि निर्धारित है। वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए कुल चार घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्या संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 75 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 73 मिनट
जनता दल (यूनाइटेड)	- 45 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 19 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	- 12 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	- 5 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 4 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	- 3 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	- 2 मिनट
सी0पी0आई0	- 2 मिनट

इंडियन नेशनल कांग्रेस से माननीय सदस्य श्री आनंद शंकर सिंह । 19 मिनट ।

श्री आनंद शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद ।

महोदय, बजट की जो यह प्रस्तावना पेश की गई है, निश्चित रूप से सरकार द्वारा 6 सूत्रों की बात की गई है और पहला ही सूत्र है स्वास्थ्य । मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा हमलोगों को यह बताया गया कि 11.80 करोड़ लोगों का टीकाकरण करवाया जा चुका है और सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में या अन्य संबंधित चिकित्सकीय संस्थानों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की व्यवस्था करायी जा रही है । निश्चित रूप से हम बड़े-बड़े अस्पतालों के भवनों का भी निर्माण कर रहे हैं लेकिन एक समस्या जो हमलोगों को आज भी महसूस होती है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की जो संख्या चाहिये होती हैं, कहीं न कहीं उसमें भारी अंतर है । छोटे से छोटे जो जिला अस्पताल हैं, हमारे यहाँ का ही औरंगाबाद का एक उदाहरण ले लीजिये, 52 चिकित्सकों की आवश्यकता है । मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 सालों में कभी भी वे सारे पद भरे नहीं गये हैं । कहीं न कहीं चिकित्सकों का घोर अभाव रहता है । हम बहुत बढ़िया भवन बना लें, बहुत सारे लैब इस्टेबलिश करवा लें, संयत्र लगवा लें लेकिन अगर चिकित्सक नहीं होंगे तो कौन उनकी देखभाल करेंगे और कौन आम लोगों की जो चिकित्सा है, व्यवस्था है उसको हैंडल करेंगे । तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह चिकित्सकों की है और कर्मियों की है । तो मैं समझता हूँ कि उस पर भी वृहद फोकस होना चाहिए । औरंगाबाद की जहाँ तक बात है, चिकित्सा महाविद्यालय की बात हमलोग वर्षों से करते आ रहे हैं और यह जो जिला है मैं समझता हूँ कि एन0एच0 पर अवस्थित है और आये-दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और नजदीकी जो महाविद्यालय हैं चिकित्सा के, वे या तो फिर आपको गया जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको बनारस जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको पटना जाना पड़ेगा । तो निश्चित रूप से एक चिकित्सा महाविद्यालय की औरंगाबाद को भी आवश्यकता है । मैं आपलोगों के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से आपलोगों से यह आग्रह करता हूँ कि चिकित्सा महाविद्यालय की वहाँ भी स्थापना हो । महोदय, भवन निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होगा, डॉक्टरों के पदस्थापन से, व्यवस्था में कड़ाई से यह होगा । अभी कुछ दिनों पहले हमलोग बैठे हुये थे, बात हो रही थी, सिविल सर्जन वहाँ उपस्थित थे, मैं समझता हूँ कि इतनी सारी महिला चिकित्सकों

के बावजूद भी महिलाओं का ऑपरेशन जो होता है, गायनी का ऑपरेशन जो होता है वह सरकारी अस्पतालों में नहीं संभव हो पाता है । तो कहीं न कहीं व्यवस्था में भी ढिलाई है और उस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार या तो वहाँ के सिविल सर्जन होते हैं और नहीं तो वहाँ के सदर अस्पताल के जो अधीक्षक होते हैं, वे होते हैं । तो व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक हो रही है, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । निश्चित रूप से राज्य सरकार ने कोरोना में बहुत उपलब्धि हासिल की है, ऑक्सीजन का कहीं भी हमलोगों के क्षेत्र से तो ऑक्सीजन कैमूर तक, भभुआ तक, जहानाबाद तक, गया तक गया है । लेकिन यह भी एक विषय है कि हर जगह जब यह ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लग जायेंगे तो उस ऑक्सीजन जेनरेशन का आखिर हम करेंगे क्या ? हम इतने ऑक्सीजन जो जेनरेट करेंगे, उसका हम करेंगे क्या ? क्या उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है कि उसको हम कैसे खपत करेंगे ? क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है, यह परिस्थिति तो उस समय जेनरेट हुई जब कोरोना पीक पर था और हमलोगों को यह मालूम नहीं था कि यह फिर आयेगा, वृहत रूप से आयेगा या उसकी इंटेंसिटी कम होगी, यह हमलोगों को पता नहीं है लेकिन अभी तो जो थर्ड वेव का जो हमलोगों को लग रहा है, इंटेंसिटी कम है । तो वह जो ऑक्सीजन का जेनरेशन होगा तो उसका हमलोग कहाँ यूज करेंगे, इसपर भी फोकस होना चाहिए ।

महोदय, दूसरा सूत्र है शिक्षा । मैं समझता हूँ कि इसमें एक अच्छी पहल है कि माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में भवन निर्माण हेतु इसमें व्यवस्था की गई है 7530 करोड़ की स्वीकृति दी गई है । निश्चित रूप से सराहनीय कदम है लेकिन फिर वही दिक्कत, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की उपलब्धता होनी चाहिए उसी प्रकार से, अगर हम केवल भवन बनाने के लिए करें तो कहीं न कहीं वह बेमानी लगती है, जब शिक्षकों का ही पदस्थापन न हो, शिक्षकों की समुचित संख्या न हो और प्राथमिक विद्यालय का तो आलम यह है कि छोटे-छोटे बच्चों को, मैं समझता हूँ कि दो-दो कि0मी0, तीन-तीन कि0मी0, बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय भवनविहीन हैं तो उनके बच्चों को दूर जाना पड़ता है, दूसरे गाँवों में जाना पड़ता है, कहीं-कहीं तो सड़क पार करके जाना पड़ता है, वैसी परिस्थिति में बच्चों के साथ खतरा रहता है । तो एक तरफ हम प्राथमिक विद्यालयों के ही भवन का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों की । जब प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा ही ठीक से ग्रहण नहीं करेगा तो आगे की शिक्षा का क्या मतलब रह जाता है ? टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल निश्चित रूप से होना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग पर फोकस होना चाहिए, इन सब विषयों

पर, हमलोग बहुत सारे स्मार्ट क्लासेज लगाये गये हैं, मैं समझता हूँ कि कई स्मार्ट क्लासेज के उद्घाटन में भी हमलोग गये हैं लेकिन आज की परिस्थिति देखियेगा तो मालूम चलेगा कि कहीं चोरी हो गई स्मार्ट क्लास के सामानों की, कहीं बैट्री नहीं है तो कहीं कुछ हो गया । उसकी भी व्यवस्था हमलोगों को पूर्ण करवानी पड़ेगी और कोरोना के इस काल में टेक्नॉलोजी की जो सम्भावनाएँ बढ़ी हैं, ऑनलाईन क्लासेज का प्रचलन बढ़ा है तो उस टेक्नॉलोजी के माध्यम से हमलोग शिक्षा की व्यवस्था और वृहद पैमाने पर मैं कह रहा हूँ, कोशिश तो की गई है लेकिन उसको और वृहद पैमाने पर ले जाने की आवश्यकता है । इसलिये उस ओर भी सरकार का ख्याल जाना चाहिए । जहाँ तक बजट की बात है, मैं समझता हूँ कि टेक्नॉलोजी पर भी इस बजट से खर्च होनी चाहिए ।

तीसरा सूत्र उद्योग से संबंधित है, महोदय । निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार फोकस तो कर रही है लेकिन उसका फलाफल अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है । सबसे बड़ी तो दिक्कत यहाँ पर है कि राज्य सरकार के पास अपना कोई लैंड बैंक नहीं है जिसपर उद्योग-धंधे स्थापित किये जा सकें । तो उसपर राज्य सरकार का फोकस होना चाहिए, जो भी उद्यमी हैं, जो उद्योग-धंधे लगाना चाहते हों, उनको रियायती दर पर जमीन मुहैया करायें उद्यमियों को या वैसे इंडस्ट्रीयलिस्ट को जो बिहार आना चाहते हैं, पहले तो वे आना नहीं चाहते हैं और अगर आना भी चाहते हैं तो भ्रष्टाचार और यह जमीन की अनुलब्धता के कारण बोरिया-बिस्तर समेट कर वापस चले जाते हैं । तो यह सबसे बड़ा जो विषय है वह जमीन का है ।

..क्रमशः..

टर्न-14/आजाद/03.03.2022

..... क्रमशः .....

श्री आनन्द शंकर सिंह : भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से इसमें इतना ज्यादा है कि जो लोग उद्योग-धंधा यहां पर स्थापित करने के लिए आते हैं, घुमकर के पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण लौटकर चले जाते हैं तो कहीं न कहीं यह सबसे बड़ा जो लैकूना है इस विभाग और उद्योंग-धंधे स्थापित करने में, उसमें सबसे बड़ा जो लैकूना है, वह जमीन का हमारे यहां है । जमीन का लैंड बैंक उपलब्ध कराइए और उद्यमियों को उचित दर पर जमीन उपलब्ध कराइए । इसमें जो डाटा दिया गया है महोदय, मैं समझता हूँ कि 15986 नये उद्यमियों के द्वारा 800 करोड़ रू0 निवेश किया गया है । दूसरा डाटा यह है कि 4000 महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया, 4000 अत्यंत पिछड़ी जाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया और उसके

बाद दिया गया है 3999 अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया है। जो डाटा 4000 और 3999 के बीच में ही रह जा रहा है महोदय, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं यह खानापूरी की गई है और 4000-4000 यह एकुरेट डाटा चाहे महिला उद्यमियों की बात हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति के उद्यमियों की बात हो, चाहे एस0सी0/एस0टी0 उद्यमियों की बात हो । 3999 से 4000 यह तो महोदय लग रहा है जैसे लिख दिया गया है, इसमें कहीं न कहीं पदाधिकारियों की उदासीनता दिखती है । चौथा जो सूत्र है महोदय, इसमें आया है कि कृषि से संबंधित क्षेत्रों का निश्चित रूप से इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मेंशन किया गया है कि अतिरिक्त रोजगार के लिए किसी भी उत्पाद को अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की व्यवस्था की बात की गई है इस बजट में । मैं तो समझता हूँ कि कृषकों को अपने ही क्षेत्र में अगर उनका उत्पादन बिक जाय तो बहुत बड़ी बात होगी लेकिन हम अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन बेचने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह कहीं से भी मैं समझता हूँ कि उचित प्रतीत नहीं होता है । आज जो किसान अपना धान उत्पादन कर रहा है, वह भी उससे उचित दर पर एम0एस0पी0 पर नहीं लिया जा रहा है । पैक्स के जो सहकारी समितियां हैं, उनका लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो सरकार के द्वारा रेट तय की जाती है उससे 400-500रू0 प्रति क्विंटल कम दिया जाता है, उसपर सरकार नहीं चेत रही है तो किसानों को यह ख्वाब दिखा रही है कि आपका जो उत्पाद है, हम उसको अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचवाने का काम करेंगे, यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है । खाद की समस्या से हम सभी लोग अवगत हुए हैं । जिस प्रकार से खाद की किल्लत हुई है और मैं देख रहा था, सुन रहा था सुबह में ही एक प्रश्न आया था और माननीय मंत्री जी का जो बयान आया था कि सब जगह खाद उपलब्ध करा दिया गया था । मैं खुद औरंगाबाद जिला से आता हूँ और वहां पर खाद के लिए इतनी मारा-मारी और कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि प्रशासन द्वारा किसानों को लाठियों और डंडों से मारा जा रहा है । जब खाद उपलब्ध था तो फिर आप किसानों को लाठी और डंडों से मार रहे हैं । कहीं-कहीं तो ऐसा भी देखा गया कि कोई किसान 20 बोरा खाद दूसरे राज्य से लेकर आया है तो उसपर छापा मारा जा रहा है । वह किसी तरीके से दूसरे राज्य से खाद लेकर उपलब्ध कराया है तो उसपर भी छापामारी चल रही है तो कहीं न कहीं आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में माल बेचवाने की बात करते हैं और किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पाते, उनका जो फसल होता है, धान होता है, गेहूं होता है, उसको भी बेचने की व्यवस्था आपकी नहीं है । उसको भी

एम0एस0पी0 नहीं मिलता है तो आप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो यह कहीं न कहीं बेईमानी है ।

जिस प्रकार से तीन काले कानून आये, मैं समझता हूँ कि किसानों के द्वारा अगर इतना लम्बा-चौड़ा विरोध नहीं किया जाता तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों कानून वापस नहीं होते । कल तक हमारे मित्रगण उसी काले कानून के बारे में प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे लेकिन आज जब वापस हो गया तो उनके बारे में जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते । मैं समझता हूँ कि यह सरकार कितनी किसानों के प्रति सजग है वो इनकी मनोदशा का बयान करती है ।

हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था की बात करते हैं, किसान तब न खेती करेगा जब सिंचाई की व्यवस्था होगी । हरियाही परियोजना हो या उत्तर कोयल परियोजना हो, सभी परियोजनायें लंबित थी और 2015 के चुनाव में जब मोदी जी गया आये थे मगध की धरती पर तो उन्होंने कहा था कि जब तक आप लोगों के खेतों में लाल पानी नहीं पहुँचा दूँगा, तब तक मैं दोबारा आपलोगों से वोट मांगने नहीं आऊंगा । दोबारा अब क्या सर 2020 का भी चुनाव पार कर गया, 2019 का भी चुनाव पार कर गया और दोबारा भी आये लेकिन आज तक किसानों के खेतों में लाल पानी नहीं आया तो उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । इन मुद्दों को आज अन्तर्राज्यीय मुद्दा बनाकर इतनी ढ़िलाई बरती जा रही है, उन पदाधिकारियों पर भी दोषारोपण होना चाहिए आखिर क्या कारण है कि बिहार सरकार द्वारा राशि मुहैया कराने के बाद भी उदासीनता बरकरार है । आज तक औरंगाबाद हो या गया हो या जहानाबाद हो ....

(व्यवधान)

भाई साहेब, उस समय डबल ईंजन की सरकार थी और झारखंड में भी आपकी सरकार थी और उसके बावजूद भी लाल पानी औरंगाबाद के किसानों को, जहानाबाद के किसानों को या गया के किसानों को नहीं मिल पाया । आप खेतों में सिंचाई की बात करते हैं तो कहां से होगा, जब आपकी परियोजनायें पूर्ण नहीं होगी... (व्यवधान)

देखिए मुँह मत खोलवाइए, निश्चित रूप से आपका एन0डी0ए0 का गठबंधन बड़ा मजबूत है । लेकिन कल हमारे मित्र बोल रहे थे तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि गठबंधन तो जोरदार है लेकिन गठबंधन के भी कुछ नियम होते हैं । गठबंधन के नियमों पर मैं समझता हूँ कि आपलोग सफल नहीं हैं । सरकार के मंत्री कुछ और बोलते हैं, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलते हैं और दोनों का एक-दूसरे के बातों से इतेफाक नहीं होता । यह कहीं न

कहीं कमी है । एक ईंजन आगे खिंच रहा है और दूसरा ईंजन पीछे खिंच रहा हैं। इसलिए कहीं न कहीं आपलोग एक-दूसरे पर इतेफाक नहीं रख रहे हैं तो आपलोग इतेफाक रखिए । गठबंधन का मतलब विचारों का भी गठबंधन होता है तो मुख्यमंत्री जी के विचारों से और जदयू के विचारों से इतेफाक रखिए, आपलोग इतेफाक नहीं रखना चाह रहे हैं । जिस प्रकार से यह सारी बातें हो रही है ।

महोदय, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है (व्यवधान)

भाई, गठबंधन समस्याओं पर एकमत होने पर गठबंधन होता है, कार्यक्रमों, नीतियों और विचारों का गठबंधन होता है .....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : आपलोगों का न तो नीति मिल रहा है, न विचार मिल रहा है और न समस्या एक है, सब कोई एक-दूसरे को, स्थिति यही है । यह गठबंधन आपके परिस्थितियों का गठबंधन है, आपलोग भी समझते होंगे । इसलिए समझिए इन चीजों को ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने 19 मिनट में दो माननीय सदस्यों का नाम दिया था।

अध्यक्ष : एक ही आदमी का नाम आया, इनको समय 19 मिनट दिया गया, अब आप बैठ जाइए ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : धन्यवाद सर, लेकिन एक बात सुन लीजिए महंगाई पर -

सखी सैईया तो बहुते कमायेत हय,
महंगाई डाईन खाय जायत हय ।
इसके चलते सभी लोग त्रस्त हैं ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया है ।

आज माना कि इतना आसान नहीं
इस सपने को हकीकत हो जाना,
लेकिन जिद है कुछ पाने की,
तो इतना कठिन भी नहीं है,
सपने को हकीकत में बदल जाना ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट का पूरा आकार का समग्र बजट पेश किया गया है, इसमें चौतरफा विकास का चिंतन हुआ है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, ग्रामीण

विकास को विशेष ध्यान दिया गया है । बिहार के लगभग 2,37,651.19 करोड़ रू0 का वर्तमान बजट से स्पष्ट है कि किस प्रकार यह बजट सरकार के सामाजिक क्षेत्र और ढाँचागत विकास को अपना आवंटित केन्द्र किया है । इस बार के बजट में सामाजिक सेवा पर 40.20 प्रतिशत, आर्थिक सेवा पर 25.25 प्रतिशत और सामान्य सेवा पर 27.82 प्रतिशत का आवंटन रखा गया है । यह बजट दर्शाता है कि सरकार का बजट का बड़ा हिस्सा है । अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्तर्गत महिलाओ, प्रक्रिया युवाओं सबका चिंतन मनन हुआ है । आज आपका ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहेंगे

..... क्रमशः .....

टर्न-15/शंभु/03.03.22

श्री संजीव चौरसिया : ..क्रमशः.. कि इस बजट के आकार में कोरोना के कार्यकाल में भी वृद्धि, जहां संपूर्ण देश में अलग-अलग प्रकार से डगमगाती हुई दिखायी दे रही थी, आर्थिक वृद्धि दर्ज की गयी है 2.5 प्रतिशत का विकास दर हमने हासिल किया है । शिक्षा के क्षेत्र में जिन छः बिन्दुओं पर माननीय महोदय कह रहे थे अगर देखने का चश्मा विकासात्मक दृष्टिकोण से रखेंगे तो विकास ही विकास नजर आयेगा । इन छः बिन्दुओं पर अलग-अलग प्रकार से अगर शिक्षा में हम देखते हैं तो लगभग 16.50 प्रतिशत की वृद्धि पूरी मजबूती के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का किया गया है । जब हमलोग विद्यार्थी परिषद् में थे तो सरकार से उस समय मांग करते थे कि बजट का छः प्रतिशत हो, लेकिन आज बजट का 16.50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार के तरफ से दिया गया है । जो अपने आप में शिक्षा जगत का बढ़ता हुआ कदम है । इसके अन्तर्गत 39 हजार 191 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । यानी कि शिक्षा पर 3.44 प्रतिशत की वृद्धि पिछली बार हुई है । लगभग 6298 प्लस टू स्कूलों के भवन के लिए 7530 करोड़ रूपये की मंजूरी की गयी है । 6421 माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गयी है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के पूर्व और पश्चात् जब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो 1886 में स्थापित जो इंजीनियरिंग था उसकी भी संख्या आप देखेंगे तो नगण्य प्रकार से थी । 2004 में एन0आइ0टी0 का गठन और आजादी के पश्चात् अलग-अलग प्रकार से जो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है । आज आप शिक्षा के आकार को देखेंगे डिजिटल के माध्यम से हो चाहे शिक्षा के पूरे भारत के मापदंड के हो तो हमने विश्वविद्यालय का निर्माण करने का भी काम किया है और शिक्षा के अनेक बिन्दुओं को छूने का काम किया है । वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए अगर हमलोगों ने टीकाकरण

के दृष्टि से लगभग 11.80 करोड़ अलग-अलग प्रकार से फस्ट डोज और सेकेंड डोज देने का काम किया है । यह अपने आप में देश का अभूतपूर्व उदाहरण है । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के दृष्टि से 16134.39 करोड़ का प्रावधान किया गया है । यानी कि इसके आकार को भी बढ़ाकर जो कि 22.2 प्रतिशत अधिक है । हम जानते हैं कि कोरोना के वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से विश्व को पूरी तरह से प्रभावित किया है और 2020 से कोरोना की महामारी से हम प्रभावित हैं, पर हमलोगों ने अलग-अलग प्रकार से जो आक्सीजन प्लांट अलग-अलग देशों में होता था और हमलोगों ने बिहार के दृष्टि से आक्सीजन प्लांट के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था करने का जो सराहनीय काम किया है और लगभग 122 जगहों पर पी0एच0सी0 आक्सीजन जेनरेशन प्लांट चालू किया है और समय-समय पर उसका उपयोग अपने आप में दृढ़ीकरण इस बात को साबित करता है । यह स्वाभाविक है कि इसके लिए मेनटेनेन्स की जरूरत पड़ेगी, सरकार अपने चिंतन से इसके मेनटेनेन्स की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी । महोदय, पांच नये मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई है इस बात का द्योतक है कि सरकार चिंतित है कि प्रत्येक कमिश्नरी से लेकर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैसे हो उसके मनन के साथ-साथ क्रियाशील भी करने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा बढ़ावा मिला है । अब तक उद्योगों के क्षेत्र में सरकार की जब चिंता होती थी तो लगता था कि दूसरे प्रांत में ही उद्योग लग पायेगा, पर बिहार का दृष्टिकोण, बिहार के विकास की किरण अब बढ़ने लगी है तो उद्योग के लिए भी निवेशक बिहार आना प्रारंभ किये हैं । इथेनॉल का प्रस्ताव जो बड़ा पूरे देश के अंदर दिखायी दे रहा है, बड़ी क्रांति की जो रचना है तो बिहार में 151 प्रस्ताव आये हैं जिसमें 17 प्रस्ताव केन्द्र को भी भेजने का काम किया है । इसके अन्तर्गत 35 करोड़ 80 लाख लीटर एकरारनामा भी हुआ है और पूरे कृषि के क्षेत्र में इससे बढ़ावा मिलेगा । इसका परिणाम यह है कि उद्योग को बढ़ावा के साथ-साथ इसके रफ्तार के लिए 1643.74 करोड़ का प्रावधान जो किया गया है । इस इथेनॉल के माध्यम से 2.60 नौकरियों का इजाफा भी निश्चित तौर पर होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरी का प्रावधान भी इस इन्डस्ट्रीज के माध्यम से होनेवाला है । जैसा कि उद्योग एक बड़ा केन्द्र बिन्दु बिहार की ओर आकर्षित होते जा रहा है । इसमें डबल इंजन सरकार का ही लाभ है कि केन्द्र और राज्य मिलकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं । कृषि के क्षेत्र में जब देखेंगे कृषि के खाद्य संस्करण और कृषि निर्यात नीति से खेती किसानों की हालत सुधरेगी । इस क्षेत्र के विकास के रफ्तार के लिए 7712.30 करोड़ का

प्रावधान है । राज्य सरकार के द्वारा कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप जो जारी किया है उससे अनेक प्रकार के लाभ चूंकि विगत वर्षों में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी और हमने 2020-21 में कृषि विकास दर को 3.7 प्रतिशत जो था वह राज्य के किसान समर्थक नीतियों एवं हमारे किसान भाईयों के अथक परिश्रम का प्रतिफल है । महोदय, आपलोगों के संज्ञान में होगा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत प्रोत्साहित तालाबों के रख-रखाव हेतु 150 तालाब जीविका संपोषित ग्राम संगठन को प्रदान किया गया था । इस प्रकार से भी हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं । महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गांवो के विकास की ओर फोकस किया गया है । शहर के विकास तो हुए ही हैं, लेकिन ग्रामीण को विश्वस्तरीय सुविधा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 19739.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है । गांव में रहनेवाले लोगों को सड़क, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य समेत अनेक तरह की सुविधा देने के लिए बजट में जो ध्यान रखा गया है यह उल्लेखनीय कदम है । महोदय, कल्याण के दृष्टि से सबसे बड़ा उत्थान की जहां आवश्यकता है पिछड़ा, अति पिछड़ा सामाजिक उत्थान के लिए, एस0सी0/एस0टी0 सबके लिए सबके साथ और वंचितों के विकास के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए इस सरकार ने 12375.7 करोड़ रूपये की मंजूरी की है । एस0सी0/एस0टी0 पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, बच्चों के अलावा दिव्यांग एवं वृद्धों के लिए भी बड़ी योजना में सकारात्मक पहल किया गया है और अलग-अलग प्रकार से छात्रावासों के निर्माण के लिए भी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास अलग-अलग प्रकार से जो हुए हैं उसका बड़ा लाभ पूरे प्रकार से मिलने का हो रहा है । महोदय, सात निश्चय के तहत सरकार ने पार्ट-टू एक बड़ा हिस्सा लेकर जो बढ़ने का कदम हुआ है जो पिछली बार से इस बार भी 5 हजार करोड़ का जो आवंटन हुआ है सबसे बड़ा बल अलग-अलग प्रकार से देने का काम हुआ है । युवा शक्ति बिहार की प्रगति- बिहार के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड युवाओं को रोजगार ढूढ़ने में मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर संवाद व कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए कुशल युवा जैसे कार्यक्रम को 2025 तक चलाया जायेगा, चूंकि स्किल के माध्यम से युवा को हुनर बिहार के युवाओं को हुनर देने का काम करेंगे तो बिहार कहीं भी जाकर अपने हुनर को रोजगार के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है । यह बिहार का युवा है बिहार का नौजवान है । महोदय, युवाओं के लिए कार्यक्रम चलाये गये हैं कुल 1153 करोड़ रूपये उपलब्ध है, आर्थिक युवाओं का बल । बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम

से स्वीकृत ऋण 4500 करोड़ के लगभग 1 लाख 17 हजार 923 कार्ड निर्गत हुए हैं और अब 700 करोड़ ऋण देने का प्रावधान करेंगे । कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 225 करोड़ का प्रावधान युवा शक्ति बिहार की प्रगति को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे । सशक्त महिला सक्षम महिला- यह बिहार सरकार की संकल्पना है कि पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक पहलुओं पर राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो सभी चेतना को जागृत करते हुए जो आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इस सरकार ने किया है यह अपने आप में उल्लेखपूर्ण है । महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना इसमें उनके द्वारा लगाये जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा । सक्षम महिला उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आधी आबादी को प्रोत्साहन के लिए कुल 900 करोड़ रूपये का प्रावधान है । महोदय, हर खेत को पानी अब प्लॉट का भी सर्वे कराया जा रहा है कि सिंचाई की अधिकतम क्षमता और लक्ष्य का सही आकलन हो । इस योजना में नदियों को आपस में जोड़ने का भी काम हो रहा है जो सबसे बड़ा सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी उस योजना का साकारमुख संरचना माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है, करने का काम बिहार के अंदर हो रहा है । भविष्य में हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जायेगा । सरकार प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध इसमें 600 करोड़ रूपये किये जायेंगे । सर्वे पूरा हो चुका है, बिहार को समझन है तो नदियों को समझना जरूरी होगा इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इसे समझने की आवश्यकता को आगे बढ़ाने का काम किया है । स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव- सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी, इसकी नियमित निगरानी होगी । गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन चूंकि प्रबंधन के जो सबसे बड़ा कचरा का प्रबंधन का काम जो गांवों में करने की योजना सरकार ने तय किया है उसको हम कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम करेंगे । प्रत्येक घर से ठोस कचरा लिया जायेगा तथा नालों के अंत में निकाले हुए गंदे जल का ट्रीटमेंट भी कराया जायेगा । सरकार का ध्यान गांवों पर है इस मद में 847 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे, शहरों की तरह कचरा प्रबंधन होना है, सोलर लाइट लगना है । स्वच्छ शहर विकसित शहर- सभी शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से किये जायेंगे । ..क्रमशः..

टर्न- 16/पुलकित/03.03.2022

(क्रमशः)

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण के लिए सात निश्चय की तरफ बढ़ा है । शहरी गरीबों के लिए पर्याप्त भवन बनाये, सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृह और सबसे बड़ी रचना जो सरकार की योजना में है उससे कनेक्टिीविटी और आसान होगी । आसपास के गांव जोड़ते हुए मुख्य पथ और प्रखंड थाना, अनुमंडल, बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं नेशनल हाईवे सम्पर्कता के लिए नई सड़कों का निर्माण कराया जायेगा । शहरी इलाकों में भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिकता के आधार पर बनाने का काम हमलोगों ने किया है । प्रत्येक आठ से दस पंचायतों में पशु अस्पताल की व्यवस्था की जायेगी । लोगों द्वारा कॉल सेंटर में फोन करके और मोबाईल ऐप के माध्यम से सुविधाएं भी प्राप्त होंगी । टेली मेडिसिन के माध्यम से भी अलग-अलग प्रकार से इसके निर्माण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, जो सड़कों के निर्माण के लिए एक बड़ी संकल्पना जो बिहार में थी कि छह घंटे से हमलोगों ने संकल्पना पूरी की है अब तो और चार घंटे के अंदर भी, चार से पांच घंटे के अंदर आने का काम अलग-अलग प्रकार से जोड़ने का होगा । जे0पी0 सेतु के बारे में आपको पता होगा, दो लेन के विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वीर कुंवर सिंह सेतु को भी चार लेन, मुंगेर रेल-सह-सड़क सेतु को दो लेन तथा सात नये पुलों के निर्माण प्रगति पर हैं जिनका निकट भविष्य में पूर्ण होनी की संभावना है । बिहार का यह बजट समग्र बजट है इसके लिए हमलोग जो मानकर चले हैं वह सबसे बड़ा कदम है इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे । शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने का वाला जो राज्य को आगे बढ़ने का काम कर रहा है उसमें हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे बड़ी सुविधा के रूप में इस सरकार ने काम करने का काम किया है उन सब विषयों पर जब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आप को पाते हैं कि एक अलग-अलग प्रकार से राज्य ने विकास का जो पैमाना चलाया है जो आत्मबल शक्ति, गौरवमय इतिहास रचने का काम किया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान राज्य की सरकार ने किया है । आज राज्य की सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के लिए, म्यूजियम के उत्थान के लिए इस सबसे बड़े विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है । राज्य की सरकार में शहरीकरण के लिए, विकास के लिए अधिकतम दलों की रचना जो होती थी पूरे देश में यह दिखाई देता था कि शहरीकरण का क्षेत्र बिहार में कम बढ़ रहा है । आज बिहार सरकार ने शहरीकरण के दौर को आगे बढ़ाने का काम किया है । गांव भी बढ़ रहे हैं और शहर की

आबादी, गांव की आबादी को भी शहरीकरण के लाभ मिलने का काम हो । पटना के शहरों में भी मेट्रो की व्यवस्था से लेकर सड़कों के फोर लेन से लेकर अलग-अलग प्रकार से जो पटना रचता है, बसता है, आत्मा है बिहार की उस पटना को जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण के माध्यम से सरकार ने बजट का प्रावधान करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है वह धन्यवाद के पात्र है । आज गंगा परियोजना के माध्यम से, गंगा के क्लीन के माध्यम से डॉल्फिन जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं । वहां की डॉल्फिन जिस प्रकार से दिखाई देती है एक नेशनल हैरिटेज के रूप में डॉल्फिन वहां दिखाई देती है । इस रचना को सरकार ने योजना के तहत उसको ग्रीन डॉल्फिन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया है । सरकार की यही संकल्पना है उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है । अध्यक्ष महोदय, आज सब विषय पर सांस्कृतिक विरासत के विषय पर, आर्थिक विरासत के विषय पर और उच्च शिक्षा के विषय पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार ने की है आज अभिनन्दन के पात्र इस बजट के माध्यम से हम सबको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और तो और जब हम कृषि के विकास की ओर देखेंगे क्योंकि बिना किसान के बिहार का विकास संभव नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से मुफ्त बिजली से लेकर, फीडर से लेकर अनेक योजनाओं को किया है, यह मन का भाव है । इस आस्था की जब व्यवस्था का काम सरकार ने किया है उसके लिए अभिनन्दन है पर आस्था की व्यवस्था में कुव्यवस्था की चिंता और चिंतन नहीं हो सकती है उस आस्था में व्यवस्था की ही चिंतन हो सकती है। हमको इसके बारे में चिंतन और मनन करना चाहिए । मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा कि -

''तूफानों में भी जलता रहे वह दीया बनो,
बरसात में सैलाब न लाये वह दरिया बनो,
क्योंकि सहनशीलता से विकास होता है,
और उग्रवादिता से विनाश होता है ।''

इसलिए सहनशील बनें और विकास के अग्रम कदम को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ाने का काम करे तभी विकास का पैमाना इस पूरे राज्य में दिखाई देगा, क्योंकि बढ़ता बिहार, चढ़ता बिहार, गौरवमय बिहार, बिहार के युवाओं और जो उत्थान पूरे विश्व में कर रहा है । धन्यवाद है सरकार को बिहार के बिहारीपन बढ़ाने का काम किये हैं कि अनेक प्रांतों में बिहार का बिहारीपन जाता है वह कहीं न कहीं व्यंजन के माध्यम से, प्रतिभा के माध्यम से, कला के माध्यम से, मधुबनी पेंटिंग से लेकर, भागलपुर पेंटिंग से लेकर सभी प्रकार के वह अपनी स्मृति छोड़कर

आने का काम करता है । इस स्मृति में बिहार का बिहारीपन लगातार झलकते रहता है, दिखते रहता है । आज अफसरशाही से लेकर, जो भी देखे बिहार का कीर्तिमान चारों ओर फैला हुआ है । आपने समय देने का काम किया है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई है । बिहार की अच्छाइयों की ओर देखना सीखें । जब अच्छाई नहीं दिखाई देगी, केवल चश्मे की बुराई ही बुराई दिखाई देगी तब विकास का पैमाना नहीं देख सकते हैं । इसलिए बड़ा लेंस अच्छाइयों का करें और बाई-फोकस करके देखें तो विकास की नजदीकियां, दूरियां दोनों दिखाने का काम करेगा । तब माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग दोनों प्लानिंग हमने करके आगे बढ़ाने का काम किया है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संदीप सौरभ ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो बजट प्रस्ताव लाया गया है, उसको देखने के बाद अदम गोंडवी की दो पंक्ति याद आती है -

''कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी हैं ।''

जो फर्जीवाड़ा बजट प्रस्ताव में है, उसके कुछ बिन्दुओं की तरफ मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । बजट में सरकार को केन्द्र से जो मिलने वाले टैक्स में शेयर है उसको 91,181 करोड़ रुपये दिखाया है, लेकिन कुछ दिनों पहले जब यूनियन का बजट आया, केन्द्र सरकार का जो बजट आया था उसमें केन्द्र सरकार ने बिहार को जो टैक्स वाला हिस्सा देने की बात कही वह सिर्फ 82,139 करोड़ का है । यानी 10 प्रतिशत का फर्जीवाड़ा टैक्स को बढ़ाकर के दिखाने के लिए आमद को बढ़ाकर दिखाने के लिए सरकार ने किया । इसी प्रकार से बिहार सरकार जो अपना टैक्स वसूलती है उसमें 18 प्रतिशत का इजाफा दिखाया गया है, लक्ष्य के रूप में । जो किसी भी अर्थशास्त्री से बात की जाय तो यह संभव नहीं है । वर्तमान स्थिति में यह बिहार में संभव नहीं है । सवाल यह उठता है कि यह बार-बार टैक्स को बढ़ाकर के दिखाने का, आंकड़ों से खेलने का सरकार का जो रवैया है इसका असल में जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, वह बिहार की जनता को भुगतना पड़ता है । पिछली बार सरकार ने शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति के ऊपर जो बजट एलोकेट किया था, सदन के अंदर, वह 39,351 करोड़ रुपये था लेकिन जो वास्तविक एलॉटमेंट हुआ वह 31 प्रतिशत कम हुआ क्योंकि आपने बजट के समय दिखाया कि हमारे पास खूब पैसा आ रहा है

और जब बजट एलोकेट करना था शिक्षा डिपार्टमेंट को तो आपने सिर्फ 27,347 करोड़ ही एलॉट किया । इसी तरह से एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सरकार ने जो बजट की घोषणा सदन के अंदर की उसमें 76 परसेंट की कटौती करते हुए बजट एलोकेट किया गया और ऐसे तमाम आंकड़े यहां पर हैं जो सरकार के लिफाफेबाजी का और बजट में जो दिखावटीपन किया गया है वह हमारे सामने है । महोदय, रुरल डेवलेपमेंट के ऊपर पिछली बार सरकार ने बजट एलॉटमेंट से जो वास्तविक बजट दिया था उसमें वह 40 प्रतिशत कम रहा । इसी तरीके से एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिवीटिज में 52 प्रतिशत की कटौती हुई तो इस तरह से हम आंकड़ों पर नहीं जाते बल्कि जो ज्वलंत सवाल बिहार के हैं और जो बजट से और सरकार की मंशा से जो चीजें गायब दिख रही हैं उसकी तरफ हम सरकार का इस सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं । वह निश्चित तौर से रोजगार का मसला है । जो हाल में एन0एस0ओ0 का आंकड़ा है नेशनल स्टेस्टिीसटिकल ऑफिस का जो आंकड़ा है, वह यह कह रहा है कि 15 साल से लेकर के 59 साल की आयु में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेश्यो है वह बिहार में सिर्फ 27.5 प्रतिशत है । सिर्फ इतने लोगों का ही लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन एस0जी0डी0पी0 बजट में हो रहा है । इसका सीधा मतलब है कि बड़े हिस्से के पास कोई रोजगार नहीं है यह राष्ट्रीय आंकड़ा 41 प्रतिशत के आसपास है । रोजगार की बात करते हुए मुझे हाईकोर्ट का एक जजमेंट जो पिछले साल 15 जुलाई को आया था, मैं उसको कोट यहां पर करना कहा था । माननीय हाईकोर्ट के वर्डिक्ट में एक बात आई थी कि भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बे-दिमाग अर्थात् माइंडलेस नहीं है जितनी बिहार की सरकार । अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई भी संस्थान इतनी बेशर्मी नहीं कर सकती है, जितनी की बिहार की सरकार । ये हाईकोर्ट ने क्यों कहा ? शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एक मसले पर रिट पिटीशन के जवाब में यह हाईकोर्ट ने कहा था और हम देख रहे हैं कि आज बिहार में तमाम ऐसी बहालियां हैं जो सरकार के माइंडलेसनेस के चलते लाखों अभ्यर्थियों का जीवन, उनके भविष्य को अंधकारमय बनाया जा रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न-17/अभिनीत/03.03.2022

-क्रमशः-

श्री संदीप सौरभ : एस0टी0ई0टी0 की बहाली 2019 की बात अगर करें तो इसमें सरकार की तरफ से 37 हजार बहालियों में हमें लगता है कि 37 बार गलतियां की गयी हैं ।

पहली बार 12 मार्च को जो रिजल्ट आया कहा गया कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाय, सबकी नौकरी पक्की समझी जाय । माननीय शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने और शिक्षा विभाग के तमाम आलाधिकारियों ने प्रेस-कांफ्रेंस करके यह बात कही । अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में वो जो एस0टी0ई0टी0 की विज्ञप्ति थी उसकी धज्जियां उड़ाते हुए बार-बार बयान बदले जा रहे हैं । महोदय, मुझे दो-तीन बातें और कह लेने दी जाय ।

अध्यक्ष : आपको छः मिनट का ही समय दिया गया है ।

श्री संदीप सौरभ : बी0एस0एस0सी0 इंटर स्तरीय बहाली में महोदय विज्ञप्ति को न मानते हुए 2014 के पहले का एम0सी0एल0 मांगा जा रहा है । अनियोजित कार्यपालक सहायक जो हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति की जाय और उनका काम सिर्फ वही करें । इसके बावजूद सरकार उनका काम शिक्षकों से ले रही है । सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ का मामला है महोदय, जिसमें 2017 में उनके बच्चे जो माननीय मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में आंदोलन कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सांख्यिकी के बच्चे हो झंडा नीचे करो नहीं तो सड़क पर ला देंगे और आजतक उनको काम नहीं मिल रहा है, उनकी बहाली रूकी हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बैठ जाइये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, बस तीन संटेंस । महोदय, मैं सिर्फ तीन वाक्त बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा । मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार में एक पॉलिसी बने जिसमें हर बहाली की विज्ञप्ति में विज्ञप्ति के अंदर यह नियम बनाया जाय कि विज्ञापन कब पूरा होगा, उसकी समय-सीमा का उल्लेख हो, एक बात ये । दूसरी बात, जो वर्तमान में बिहार के अंदर रोजगार की स्थिति है, जो बहालियों का संकट है उसको दिखाते हुए आगे का रोडमैप सरकार की क्या होगी इसके ऊपर एक शेध पत्र सरकार जारी करे कि वह कबतक उसको शार्टआउट करेगी । तीसरा मामला है महोदय, युवाओं का संकट जो बिहार में दिख रहा है सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है, इसको लेकर सरकार क्या सोचती है ? इसे लेकर मुझे लगता है, मेरे ख्याल से एक अतिरिक्त सदन, विधान सभा का एक अतिरिक्त सत्र जिसमें रोजगार और तमाम जो 22 तरह की बहालियां बिहार में पेंडिंग पड़ी हुई हैं विभाग और सरकार के मनमानेपन के चलते उसको लेकर एक अतिरिक्त सत्र हो । यही मैं सरकार से कहना चाहता हूं । आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सुश्री श्रेयसी सिंह ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, बजट 2022-23 पर अपने विचारों को सदन पटल पर रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आसन के माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिनंदन करती हूं ।

एक समाज के रूप में कोरोना महामारी के कारण जिन परिस्थितियों को हमने झेला है उसका मर्म महान शायर जॉन एलियो की दो पंक्तियों से बयान करना चाहती हूं ।

''कौन सीखा है सिर्फ बातों से,
सबको एक हादसा जरूरी है ।''

अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने हम सबके जीवन में बड़े बदलाव ला दिए हैं । हम सबने अपनों को खोया है । बिहार में करोना संक्रमण के कारण कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है । यहां पचास हजार रुपये की दर से अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है जिसे केंद्र सरकार के आपदा राहत मद ने अनुमान्य किया है । बिहार एक मात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण में मृत व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है । राज्य में मुफ्त कोविड टेस्ट भी किये जा रहे हैं । स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में विगत दो साल से काफी सुधार हुआ है । बिहार में 11.280 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है । सौ से ज्यादा जगहों पर ऑक्सिजन प्लांट को शुरू कराया गया है । करोना महामारी से लड़ने के लिए हमारी तैयारी पूरी है और हम मजबूत हैं । यह हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के सौष्ठव को प्रकट करता है । इसके अलावा भारत सरकार ने बिहार को अपेक्षित सहायता प्रदान की है । राजकोषीय असंतुलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण लेने की सीमा में भी बढ़ोत्तरी की है । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार वर्ष 2020-21 के दौरान पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर था । विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा । बिहार सरकार ने 2.37 लाख करोड़ का बजट पेश किया है । इस बार बजट में आधारभूत संरचना का विकास, रोजगार सृजन और कोविड के कारण पिछले दो वर्ष में स्थिर रहे आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उद्यमिता विकास और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है । इस बजट में पूर्व से चली आ रही सात निश्चय-1 की योजनाओं को पूर्ण करने के साथ तथा सात निश्चय-2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है एवं इसके लिए राशि की भी व्यवस्था की गयी है । इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय और वर्गों का विकास

संभव होगा । सामाजिक विकास को लेकर सरकार कितनी गंभीर है यह इस बात से समझा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65 फीसदी खर्च होगा । अध्यक्ष महोदय, गौर करने वाली बात है कि 2004-05 का बजट मात्र 23 हजार 885 करोड़ का था लेकिन इस बार बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने यह बजट बढ़ाकर 2 लाख 37 हजारा 691.19 करोड़ रुपया का किया है । मतलब पिछले 16 वर्षों में बजट ने दस गुणा बढ़ोत्तरी किया है । जाहिर है कि बजट की राशि बढ़ेगी तो बिहार के विकास के कार्यों में भी इसकी झलक दिखायी देगी और 90 के दशक से आज के बिहार को नजदीक से देखने वाले ये लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके खेतों की सिंचाई । इसके लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि हर घर, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है । इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पहले चरण का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है । युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत प्रथम फेज में राज्य के सात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध किया गया है । बिहार में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और साथ-साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भी कानून बनाया गया है । स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया भी चालू है । अध्यक्ष महोदय, युवा शक्ति को बल देते हुए वर्ष 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजनांतर्गत अबतक कुल 657 करोड़ की राशि वितरित की गयी है । वर्ष 2022-23 में इस योजनांतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है । यही नहीं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत वर्तमान में कुल 1496 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं । अभी तक इस योजना पर 702 करोड़ व्यय हुआ है और वर्ष 2022-23 में इस योजनांतर्गत 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था तब राज्य में हरित आवरण का क्षेत्र मात्र नौ फीसदी रह गया था जबकि आज हरित आवरण का क्षेत्र बढ़कर 15 फीसदी के करीब पहुंच गया है । बिहार सरकार इतनी इको फ्रेंडली है कि...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब संक्षिप्त कीजिए ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : जन-जीवन हरियाली अभियान चलाया और विश्व में सबसे बड़ी मानव शृखंला का निर्माण किया गया । साथ ही, जन-जीवन हरियाली के लिए 24 हजार

करोड़ की राशि भी प्रदान की गयी है । अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से, इस आसन के माध्यम से, एक युवा होने के नाते, एक नारी होने के नाते मैं माननीय वित्त मंत्री-सह-उप मुख्यमंत्री जी को तहेदिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बजट में युवाओं का, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मनोज मंजिल । आपका चार मिनट का समय है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, बजट का जो सत्य है उसे मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं । सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आयी है कि देश में आठ प्रतिशत बेरोजगारी दर है और बिहार के गांवों में साढ़े 13 प्रतिशत और शहरों में 18 प्रतिशत बेरोजगारी दर है । साढ़े चार करोड़ युवा बेरोजगार हैं, बिहार में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है ।

-क्रमशः-

टर्न-18/हेमन्त/03.03.2022

...क्रमशः..

श्री मनोज मंजिल : देश में आधी आबादी मात्र साढ़े चार हजार की कमाई पर गुजारा कर रही है । 84 प्रतिशत लोगों की आमदनी घट गयी और देश में 102 से 145 अरबपति हो गये । बिहार में चाहे विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, बैंक, कोई भी आप विभाग उठा लीजिए, 60 से 70 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री जी पीठ थपथपा रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहे हैं । बहुत शिक्षक की बहाली कर दिये । अरे, तीन साल में मात्र 37 हजार शिक्षकों की बहाली किये । साढ़े तीन लाख पद खाली पड़े हैं पूरे बिहार में । नौजवान, जवानी बर्बाद होती जा रही है नौजवानों की, ये सरकार जवानी खा रही है, नौजवानों के सपने मार रही है। उम्र बीत जा रही है । अरे, कौन लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर गये थे आंदोलन करने। ये वही बच्चे हैं, मजदूर किसानों के, खून-पसीने के, खेत-खलिहानों के, गरीबों की संतान हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते, जो प्रोफेसर नहीं बन सकते, वकील, जज, डीएम, एसपी नहीं बन सकते, उन्हीं के बच्चे तो मास्टर बनना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, अस्पतालों में नौकरी करना चाहते हैं स्टाफ में और सरकार बहाली नहीं कर रही है । केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में रिपोर्ट आयी 8,72,243 पद खाली पड़े हैं । जब बहाली नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं, भर्ती नहीं, तो आरक्षण कहां से ? आरक्षण की हत्या हो रही है बिहार और पूरे देश में । इसके लिए हम मांग करते हैं इस सरकार से कि यह नहीं चलेगा कि बिहार स्टाफ सलेक्शन कमीशन का, 2014 की बहाली

13,120 का अभी तक लटका कर रखे हैं । जो बच्चे फॉर्म भरे थे, परीक्षा दिये थे, उनके बच्चे हो गये, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ताने सुन रहे हैं मां-बाप के, गांव-जवार के और इसीलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार बहाली कलेण्डर जारी करे और हिम्मत है सरकार को, तो रोजगार पर, नौकरी पर स्पेशल सत्र बुला ले दो दिन का, पास करा ले बिहार में और शिक्षा की क्या हालत है, नौवीं क्लास के, मिडिल क्लास के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना जान रहे हैं 60 प्रतिशत से ज्यादा, अंग्रेजी की रीडिंग तक नहीं आती, मिडिल क्लास के बच्चों को जोड़, घटा, गुणा, भागा नहीं आता । अरे, कैसे उनका भविष्य बनेगा ? स्कूलों में शौचालय कहां हैं आपके ? गरीबों की बेटियां स्कूलों के पीछे जाती हैं, क्या उनकी लाज नहीं, क्या उनका सम्मान नहीं । उनका तो लाज-सम्मान है इस सरकार का कोई लाज सम्मान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में चले जाइये, पी0एम0सी0एच0 में, ओपीडी में 78 की संख्या के विरुद्ध मात्र 21 दवा हैं । आधी कमाई महंगाई में, आधी कमाई दवाई में, गरीब का खर्चा करी है बाल-बच्चा की पढ़ाई में । कितनी है कमाई और इसीलिए आज बिहार, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री मनोज मंजिल : 52 प्रतिशत लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं । महोदय, स्कूली बच्चे शिक्षा नहीं पूरी कर पाते ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री मनोज मंजिल : शिक्षा का निजीकरण हो रहा है । गरीब के बच्चों को स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से बाहर करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये माननीय सदस्य ।

श्री मनोज मंजिल : इसलिए महोदय, एक मिनट । ये बिहार गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, कुपोषण से मुक्ति चाहता है ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । श्री ललित नारायण मंडल ।

श्री मनोज मंजिल : महंगाई से, जाति धर्म और नफरत की राजनीति से यह बिहार मुक्ति चाहता है ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, अपने वित्तमंत्री जी तारकिशोर जी का..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये ।

श्री ललित नारायण मंडल : और श्रवण बाबू का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको यहां पर बोलने का मौका दिया है । अध्यक्ष जी, हमारे हर दिल अजीज वित्तमंत्री जी द्वारा जो प्रस्तुत बजट है वह काबिल-ए-तारीफ है । विरोध केवल विरोधी को करना है यह कोई नीति नहीं है, उसकी नीयति को देखना चाहिए । अध्यक्ष जी, विगत वर्षों में या तुरंत अभी जो कारोना काल गुजरा है उसमें हमारी सरकार ने क्या नहीं किया है। कोरोना को समुद्र के पास, समुद्र के पार भेजने में दिल्ली सरकार और बिहार सरकार ने सारी जुगत लगा दी और सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अभी तक 118800000 वैक्सीनेशन पूरा हुआ है । जिसके कारण कोरोना का प्रभाव बहुत कम हुआ है । दुर्भाग्य से यदि किसी परिवार में कोरोना के चलते मृत्यु हुई है, तो हमारी सरकार ने उस पीड़ित परिवार को प्रति मृत्यु पर 4 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया है और केंद्र सरकार से 50 हजार रुपये का अनुदान मिला है । यह साधारण बात नहीं है । यह बिहार है जहां पर यह 4 लाख रुपये का अनुदान मिला है और कहीं पर यह संभव नहीं है ।

अध्यक्ष जी, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

क्या नहीं हुआ है । हम भी आप ही की तरह गांव से आये हैं । सुना जाय । हम भी आप ही की तरह गांव से पढ़कर आये हैं । पहले गांव के स्कूल की क्या स्थिति थी,

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : उसको आप जानिये और अभी गांव के स्कूल की क्या स्थिति है, उसको आप समझिये ।

अध्यक्ष : आसन की ओर देखिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष जी, अभी शिक्षा की क्या स्थिति है उसको जानिये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शांति ।

श्री ललित नारायण मंडल : अरे, हम प्रोफेसर हैं, गरीब के बेटे हैं । यह साधारण सी बात नहीं है । हमने पढ़ा है, हमने मेहनत की है

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री ललित नारायण मंडल : और तब हम प्रोफेसर बने हैं ।

अध्यक्ष : बीच-बीच में उठना उचित नहीं है ।

श्री ललित नारायण मंडल : कोई पैरवी हमको नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप आसन की ओर देखकर बोलिये । आप बैठे-बैठे मत बोलिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष जी, हमने कॉलेजों में देखा है कि जब से 15 साल से हमारी सरकार बनी है, क्या लड़के, क्या लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी है । उसको हमने अपनी नजर से देखा है और हमने बहुत सारी लड़कियों को अपने हाथ से, जो मैट्रिक पास की है उसको 25 हजार रुपया और जो इंटर पास की है उसको 50 हजार रुपया का चेक अपने हाथ से दिया है । यह बिहार में संभव है और दूसरी जगह संभव नहीं है ।

साथियो, पहले क्या होता था ? हमने जो देखा है उसकी बात हम करते हैं ।

अध्यक्ष : संदीप सौरभ जी, यह उचित नहीं है । आपके भाषण को भी सभी ने गौर से सुना है, इनका भी सुनिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : राज्य में जो सात निश्चय का कार्यक्रम चला..

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ललित मंडल जी नये सदस्य हैं और उस तरफ से जो माले के सदस्य हैं लग रहा है कि बैठे-बैठे आसमान में तीर छोड़ रहे हैं । आप लोग भी जब बोलियेगा और इधर के माननीय सदस्य अगर इसी तरह से बैठे-बैठे सवाल करेंगे, तो आप लोग भी नहीं बोल पायेंगे, तो नये माननीय सदस्य का ध्यान रखिये और जिस तरह से आप व्यवस्था बना रहे हैं यह सब लोग बैठे-बैठे देख रहे हैं । इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए महोदय । वह नये सदस्य हैं, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

टर्न-19/धिरेन्द्र/03.03.2022

अध्यक्ष : बैठ जाइये, यह बहस की जगह नहीं है । सदन की गरिमा के अनुकूल आप लोगों से अपेक्षा रहती है ...

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : तीर कहां से चलेगा, तीर तो आपके पास है, तीर कहां से छोड़ेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, चलिये ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हम देखते हैं कि गरीब विद्यार्थी जो पहले किसी तरह से कंपीटिशन की परीक्षा पास करते थे और इंजीनियरिंग में, मेडिकल में एडमिशन नहीं कराते थे, आज उसको सरकार लोन देती है, क्रेडिट कार्ड देती है कि जा कर वहां एडमिशन

कराइये और लड़के एडमिशन कराते हैं । सरकार ने घोषणा किया है, अगर नौकरी लगेगी तो पैसा लौटा दीजियेगा, नहीं तो बिहार सरकार उस पैसा को पेड करेगी, तो यह गरीबों के लिए है ये सब पैसा ।

हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नाली तथा नाला का निर्माण कराया गया है । हर घर में भी, हमारा भी घर गांव में है, हम देखते हैं कि कराया गया, आपको नहीं दिखता है तो आप जानिये । हर घर बिजली की व्यवस्था की गई है । पहले याद कीजिये, उस जमाने को जब मोबाईल चार्ज करने के लिए सोचना पड़ता था, आप मोबाईल चार्ज करने के लिए सोचते थे कि किस दुकानदार का जी-हुजूरी करें कि हमारा मोबाईल चार्ज हो जाय । आज मोबाईल चार्ज करने की बात मत कीजिये, आज 24 घंटे में अधिकतम 23 घंटे तक बिजली रहती है, गांव में भी रहती है । हम गांव से आये हैं इसलिए विरोध की बात असत्य मत बोलिये ।

सात निश्चय-1 की सफलता से उत्साहित होने के बाद हमारी सरकार ने सात निश्चय-2 को सामने लाया है जिसमें पहली बात है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें 11,053 करोड़ रुपये का प्रावधान है । इसके तहत राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कानून बना है । विकसित बिहार की कल्पना इसी सरकार में हुई है, पहले क्या होता था, हमलोग जानते हैं ।

सशक्त महिला सक्षम महिला, इस योजना के तहत आज कार्य चालू है और हमारे वित्त मंत्री जी ने इसके लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । आप जाइये पंचायतों में, आप जाइये नगर निगमों में देखने के लिए, आधी आबादी महिला वहां पर अध्यक्ष के आसन पर आज विराजमान है और यह संभव अगर है तो इसी एन0डी0ए0 की सरकार के चलते । आधी आबादी आज शासन में है जिसको की आपलोग कोई वेल्यू नहीं देते थे ।

हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है, इसके लिए हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री ने 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । लगभग सर्वेक्षण ही नहीं पूरा हुआ है, हम तो देखते हैं अपने गांव में कि जहां-जहां जिस-जिस खेत पर बोरिंग हो गया है, वहां पर बिजली भी पहुंचा दिया गया है और बोरिंग से पानी निकालकर हमारे गार्जियन खेती कर रहे हैं । इसलिए हर घर-घर की बिजली की बातें छोड़ दीजिये, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दिया गया है ।

स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी ग्रामीण वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का सर्वेक्षण पूरा हो गया है । इसके लिए 887 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है, हम इसके लिए पंचायती राज मंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने हर गांव में जो स्ट्रीट लाईट लगाने की व्यवस्था किये हैं .....

उपाध्यक्ष : समय हो गया माननीय सदस्य ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, पहले क्या होता था, सारा अंधकार रहता था । आज तो गांव में लाईट की बात की जाती है, गांव की गलियों में आप जाइये और इसको लागू होने दीजिये, गांव की गलियां शहर की तरह चमकेगी, जब हर गली में स्ट्रीट लाईट लगेगी, सोलर स्ट्रीट लाईट लगेगी, तब आप इस बात को समझियेगा ।

उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस पर 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । इसके तहत डोर-टू-डोर कचड़ा का उठाव होता है । हमारा घर सुल्तानगंज जैसे छोटे कस्बे में है, रोज सुबह दरवाजा खट-खटाकर आता है, व्हीसल बजाकर आता है ....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, व्हीसिल बजाकर आता है और कचड़ा उठा कर जाता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुर्यकान्त पासवान जी । दो मिनट समय है आपका ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो बजट पेश किया है, हम समझते हैं कि यह गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी बजट है । महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो चर्चा की कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया है । आपने किया है, विद्यालय तो बनवाया है, भवन तो चमाचम है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है । मध्य विद्यालय के टीचर 10+2 में जाकर पढ़ाते हैं महोदय, ये सरकार का हालचाल है, ये सब लोग जानते हैं । महोदय, आज, 15 साल और 20 साल की बात मत कीजिये, किसान की चर्चा कर रहे थे, जहां हर खेत को पानी, हर खेत तक बिजली पहुंचा दिये हैं । महोदय, बिजली कनेक्शन पहुंचा दिये हैं लेकिन बिजली बिल का क्या हालचाल है, हमारी सरकार का इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है । बिजली बिल अनाप-सनाप आता है, हम एक बल्व जलाते हैं और जो एक फैक्ट्री चलाते हैं, उसके बराबर एक बल्ब जलाने वाले लोगों को बिल आता है महोदय, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । आज रोजगार की बात करती है हमारी सरकार कि हमने रोजगार दिया, आज हमारे गांव के विभिन्न गांवों से, आज जाकर रेलवे स्टेशन पर आप देखिये जो हमारे मजदूर बोरे की तरह लद कर चाहे वह सहरसा हो, चाहे बेगूसराय हो, खगड़िया हो, हसनपुर हो, वहां से लद

कर दिल्ली, पंजाब दूसरे-दूसरे राज्य पलायन करते हैं महोदय और यह सरकार रोजगार की बात करती है । बजट में इसकी चर्चा कतई नहीं है । महोदय, आज कोरोना महामारी की बात हो रही है । महोदय, चर्चा कर रहे थे कोरोना महामारी में हमारे आशा कर्मी, हमारी आंगनबाड़ी सेविका, हमारे तमाम लोगों ने जान जोखिम में डालकर और हमारे पीड़ित को देखभाल करने का काम किया लेकिन आज जो उनकी पारिश्रमिक होनी चाहिए, सरकार कहती है कि हम न्यूनतम मजदूरी देंगे लेकिन आज हमारे आशा कर्मी को न्यूनतम मजदूरी 1,000 रुपया मिलती है । क्या 1,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी है ? महोदय, यह बजट में प्रावधान नहीं किया गया है कि हम आशा कर्मी....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये । माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, आंगनबाड़ी सेविका और मध्याह्न भोजन कर्मी जो विद्यालय में बच्चों को भोजन खिलाने का काम करती हैं वैसे लोगों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान नहीं किया गया है । महोदय, मैं आसन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों को न्यूनतम मजदूरी देने की बात हो ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी जी ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने नेता माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष की अनुमति से, मैं आज अपने राज्य के माननीय विकास पुरुष, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार के विकास के बारे में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । मैं सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । महोदय, सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2,37,691 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया गया, उसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं को लिया गया है । महोदय, हमारा राज्य शिक्षा की दृष्टि से बेहतर बने इसलिए सरकार द्वारा इस बजट में सबसे अधिक 39,191 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है ।

क्रमशः....

टर्न-20/संगीता/03.03.2022

...क्रमशः...

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, सरकार के प्रयास के कारण समाज के वंचित दलित वर्ग के बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है । वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच

अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन में 33.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन में 50.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

महोदय, हमने पिछले दो वर्षों में कोरोना त्रासदी को देखा है । बिहार सरकार द्वारा कोरोना संकट में भी स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर नहीं होने दिया । इसी को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षा के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज्यादा राशि दी गई है । यह राशि 16 हजार 134 करोड़ है ।

सरकार राज्य में शहरों के साथ-साथ गांवों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसका सरकार ने पूरा ध्यान रखा है । सरकार ने सभी 38 जिलों में शिशु केयर यूनिट तथा 30 जिला अस्पतालों में 10-10 बेड का आई0सी0यू0 का निर्माण 122 स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए बजट में राशि खर्च करने का प्रावधान किया है ।

महोदय, समाज के समग्र विकास के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति का कल्याण आवश्यक है । बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर ने समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए भारत के संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की है । महात्मा गांधी भी कहते थे 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' । इसी को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2007 में ही एक अलग विभाग का गठन किया और इस समाज के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना मुसहर एवं भुईयां समुदाय के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, आवासीय विद्यालय योजना चलायी, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना और विकास मित्रों की बहाली हमारे मुख्यमंत्री जी के दलितों के उत्थान के सोच का नतीजा है । अभी राज्य में 9000 विकास मित्र कार्यरत हैं ।

महिलाओं के विकास के लिए महिला विकास निगम का गठन सरकार द्वारा किया गया है । महोदय, अगर सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की बात करूंगी तो समय कम पड़ जाएगा । विकास की इतनी लंबी लाइन है जो सुनाते-सुनाते भी थक जाएंगे ।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार द्वारा पेश किया गया ऐसा बजट है जो न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य बल्कि आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ रोजगार के सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा । कोरोना संकट के बाद भी वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए जिस तरह का बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है उसके लिए हमारे माननीय विकास पुरूष मुख्यमंत्री महोदय तथा उप मुख्यमंत्री महोदय दोनों ही बधाई के पात्र हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत जी ।

श्रीमती ज्योति देवी : थोड़ा सा बचा हुआ है सर, इसको शामिल कर लीजिए ।

उपाध्यक्ष : भिजवा दीजिए ।

श्री रामविलास कामत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के सामान्य बजट के विमर्श में आपने हमें समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मैं इस सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके सौजन्य से आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं । मैं इस सदन के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विमर्श के लिए मुझे मौका मिला है । अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी जो बजट पेश किए हैं, यह बजट बिहार के विकास के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होने वाला है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह बजट पेश की गई है, जिसका आकार 2.37 लाख करोड़ है आज यूं ही इतने आकार की बजट नहीं हो गई है । 2005-06 से अगर हम देखेंगे तो साल दर साल बढ़ते बढ़तें यह बजट यहां तक पहुंची है । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट सरकार के द्वारा अभी पेश की गई है, इस बजट में सबसे अधिक प्रावधान शिक्षा विभाग के मद में किया गया है । शिक्षा विभाग में 39 हजार 191 करोड़ का प्रावधान किया गया है फिर स्वास्थ्य विभाग के लिए 16 हजार 134 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है, उद्योग पर 1643 करोड़ और कृषि पर 7 हजार 712 करोड़ का प्रावधान इस बजट में की गई है, कल्याण पर खर्च करने के लिए 12 हजार 375 करोड़ इस बजट में प्रावधान किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के प्रावधान के अनुसार जो गांव के विकास की बात है इन्फ्रास्ट्रक्चर की, विकास की बात है उसके लिए भी 1550 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आंकड़ा है, जो बजट पेश किया गया है उसका जो आंकड़ा है, उसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग पर खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया है । बजट में शिक्षा पर कुल 39 हजार 191 करोड़ रुपया रखा गया है जो बजट का 16.5 प्रतिशत है । शिक्षा के कुल बजट में वर्ष 2022-23 में स्कीम मद में 22 हजार 198 करोड़ रुपया तथा स्थापना तथा प्रतिबद्ध मद में 16 हजार 953 करोड़ रुपये खर्च होंगे । बजट के प्रावधान के मुताबिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 30 हजार 620 पदों पर छठे चरण में नियोजन की कार्रवाई भी

की जाने की प्रक्रिया की गई है इस बजट में । उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की कुल 40 हजार 558 पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसका प्रावधान इस बजट में किया गया है । सभी मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर सृजित 8 हजार 386 पद बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो योजना शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया, जिसमें प्रारंभिक विद्यालयों के भवन की आवश्यकता 15 हजार 941 के विरूद्ध 15 हजार 653 विद्यालय भवन का कार्य अब तक पूर्ण कर लिया गया है, बाकी बचे भवनों का कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिया जायेगा जो इस बजट में प्रावधान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 402 करोड़ रुपये खर्च किए थे जो आगे भी जारी रहने का इस बजट में प्रावधान किया गया है । बच्चों के पोशाक को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 898 करोड़ रुपये की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से खाता में भेजा गया था जो आने वाले वित्तीय वर्ष में भी लागू रहेगा, चालू रहेगा और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ता जाएगा ।

कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए राज्य में 535 कस्तूरबा विद्यालय संचालित की जा रही है, जिसमें 50 हजार 963 बालिकाएं पढ़ाई कर रही हैं जिनकी हर सुविधा को जारी रखने का बजट में भी प्रावधान किया गया है ।

..क्रमश:...

टर्न-21/सुरज/03.03.22

...क्रमश:...

श्री रामविलास कामत : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों में उत्क्रमित एवं नव सृजित प्लस टू स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 7 हजार 530 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वास्थ्य, उसके क्षेत्र में भी कई काम करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट में जो खर्च करने का प्रावधान हुआ है वह है 16 हजार 134 करोड़ रुपये का । राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से अस्पतालों में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है । स्वास्थ्य विभाग के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य के

सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ पांच-पांच स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कुल 1 हजार 379 स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण पर कार्य चल रहा है, जो इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है । कुल 1 हजार 754 करोड़ 99 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति इन सारे कार्यों को पूरा करने में बजट में किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पी0एम0सी0एच0 मेडिकल कॉलेज को 5 हजार 462 बेड क्षमता का आधुनिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है । हम सभी जानते हैं कि यह पटना का पी0एम0सी0एच0 पूरे राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिये जो सरकार प्रयास कर रही है इसके लिये मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आई0जी0आई0एम0एस0 अस्पताल में सौ बेड का स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना तथा 1 हजार 2 सौ अतिरिक्त बेड के अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है । महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किये जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में सौ बेड के कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जो उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है । इसके लिए भी मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदय, इस बजट में उद्योग पर भी बहुत सारे काम करने के लिए प्रावधान किया गया है । उद्योग के बजट में निवेश पर 1 हजार 643 करोड़ रुपया खर्च कर राज्य में कई उद्योगों की स्थापना एवं उद्यमों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है ।

महोदय, कृषि के क्षेत्र में 7 हजार 712 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है । वर्ष 2007 से राज्य में कृषि रोडमैप के तहत कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं । इस बार भी मुर्गी पालन, मछली पालन, गोवंश एवं सहकारिता के विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है । कृषि को उद्योग से जोड़कर अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है ।

महोदय, गांव के विकास के लिए गांव में जो 80 प्रतिशत लोग रहते हैं उनकी बेहतरी के लिए, सड़क के निर्माण के लिए, उनकी हर एक सुविधाओं को

चुस्त और दुरूस्त करने के लिए इस बजट में 29 हजार 749 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे । राज्य की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है इसके लिए गांवों में रहने वाली आबादी के लिए सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं को बहाल रखने तथा बढ़ाने के लिए बजट में ध्यान रखा गया है । शहरों के लोगों के लिए भी बजट में अनेक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है जो शहर को बेहतर और सुंदर बनाने के काम आएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, कल्याण के क्षेत्र में जो इस बजट में महत्वपूर्ण आंकड़ा इसमें दिया गया है राज्य में एस0सी0, एस0टी0, पिछड़ा, अति पिछड़ वर्ग, महिला और बच्चों के अलावा दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन योजनाओं के लिए 12 हजार 375 करोड़ खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है । इन वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लागू रखने एवं नई योजना चालू करने पर यह राशि अगले वित्तीय वर्ष में खर्च किये जाएंगे ताकि इन वर्गो के लोगों को और विकास करने का मौका मिल सके, आगे बढ़ने का मौका मिल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने जिन बातों की चर्चा आपके समक्ष, इस सदन के समक्ष किया है हम समझते हैं कि इसके अलावे इस बजट में बिहार सरकार की जो अन्य निश्चय है उस निश्चय पर जब चर्चा करेंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह बजट बिहार को विकसित बिहार, सुंदर बिहार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बजट है और इस पर काम किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के जो सात निश्चय के पार्ट-1 हैं उसके तहत जो काम किये गये हैं, वह सराहणीय रहा है और उसमें हम सभी जानते हैं और कह सकते हैं कि बिहार में जो सात निश्चय-1 का कार्यक्रम चला उसमें युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो काम किया गया वह बहुत ही बेहतरीन रहा है और छात्रों को, युवाओं को आगे बढ़ने में वह काफी मददगार रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सात निश्चय पार्ट-1 में जो हर घर बिजली पहुंचाने की बात की गई वह कार्यक्रम भी ऐसे ही नहीं हो गया उसके लिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी जो पटना के गांधी मैदान से संकल्प ले करके कहे थे कि हम वर्ष 2015 तक हर घर तक बिजली पहुंचायेंगे, तभी हम वोट मांगने के लिए जाएंगे । तो इस संकल्प को पूरा करके सरकार ने दिखाया है और आज बिजली के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से

खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम जो चालू किया जा रहा है जिस पर काम शुरू हो गया है वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । किसान...

उपाध्यक्ष : समय हो गया आपका ।

श्री रामविलास कामत : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए यह खेतों तक पानी पहुंचाने का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में इस बजट में जो प्रावधान किया गया है किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचाने का इसके लिए मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं ताकि किसानों का इसका बहुत ही अधिक लाभ मिल सके, वह आगे बढ़ सकें, उनकी तरक्की हो सके, उनका...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये । माननीय सदस्या श्रीमती स्वर्णा सिंह जी ।

श्री रामविलास कामत : बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बिहार विधान मंडल के इस सत्र में माननीय वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर अपनी पार्टी कि ओर से अपने विचार को आपके समक्ष रखने के लिए उपस्थित हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में 6 सूत्रों का बजट प्रस्तुत किया गया है । महोदय, लगातार दो वित्तीय वर्ष कोरोना महामारी की चपेट में रहे देश कि आर्थिक स्थिति भी खराब हुई, बिहार का भी विकास दर गिरा । अनुमान 10.38 प्रतिशत का था पर 2020-21 में विकास दर 2.5 प्रतिशत रहा । बिहार में पॉजीटिव ग्रोथ रेट बना रहा । बजट के अनुसार बुरा दौरा पार हो गया है और अब विकास का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ेगा । सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन बनाने के लिए 16 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये का प्रावधान किया गया है । सरकार ने लोगों के जीवन को छुने वाले एवं बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने वाले सात निश्चय-2 के लिए 5000 करोड़ के बजट का प्रावधान कर अपना संकल्प दोहराया है ।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक एवं आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए काम की जाएगी ।

...क्रमशः...

टर्न-22/राहुल/03.03.2022

श्रीमती स्वर्णा सिंह : ..क्रमशः... कुल बजट का 16.5 प्रतिशत खर्च शिक्षा पर किया जाएगा । महोदय, सरकार राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है । मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अन्तर्गत वंचित वर्ग को सर्वोच्च

प्राथमिकता दी गई है । इस वित्तीय वर्ष में उद्योग एवं उद्योग निवेश मद में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है । आने वाले वर्षों में इसका असर रोजगार बढ़ाने में दिखेगा । महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं । किसानों की आय में वृद्धि करने पर भी सरकार का फोकस है । सरकार द्वारा 54 बाजार प्रांगण को विकसित करने के लिए 2046 करोड़ रुपये खर्च करेगी । दलहन और तिलहन की उपज को बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को दलहन और तिलहन के बीज भी फ्री में उपलब्ध करायेगी ।

महोदय, बिहार की आत्मा गांवों में बसती है और 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है । इसके लिए राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं ग्रामीणों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है जिसके लिए सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है । सभी गांवों में सरकार द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट लगायी जायेगी । सरकार ने इसके लिए भी समुचित धन उपलब्ध कराया है । महोदय, हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए तन-मन-धन से कार्य कर रही है । साथ ही दिव्यांगजनों वृद्धजनों एवं वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जी ने इनका भी पूरा ख्याल रखा है । महोदय, वर्ष 2020 से महामारी एवं आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार अपने विवेक से राजकोषीय प्रबंधन के द्वारा राज्य में वित्तीय असंतुलन नहीं होने दिया । इस विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर जनता के लिए अनेकों जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत एवं सतत रखने का प्रयास किया गया है । अब हम सभी को इस आवंटित राशि का पूर्ण सदुपयोग हो इसके लिए सतत् प्रयास करना है। पुनः मैं उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 सत्येंद्र यादव जी ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 2022 का अनुपूरक प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में मुझे 2-3 बातें महत्वपूर्ण रूप से कहनी हैं । हमारे साथी चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट में बिहार के युवाओं के लिए एन0डी0ए0 की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है । अच्छे काम का नमूना है कि उद्योग विभाग को पूरे बजट में 1643 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 1643 करोड़ रुपये

में 6 पार्क में 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे । मुझे यह बात कहनी है कि बिहार की 12–13 करोड़ की आबादी में 1643 करोड़ रुपये में ये कौनसी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे । बिहार मानव श्रम प्रधान राज्य है और बिहार के डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार को उद्योग को प्राथमिकता में शामिल करना चाहिए लेकिन सरकार के लोग जितने भी भाषण कर रहे हैं उद्योग सरकार की निगाहों में, प्राथमिकता में नहीं है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को उद्योगों को प्राथमिकता में लेना चाहिए और 1643 करोड़ का जो बजट है उसको बढ़ाने की जरूरत है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है बड़े लोग ताली ठोक कर कह रहे हैं, मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब आप कहते हो कि बिहार के अंदर 24 घंटा बिजली देते हैं तो सोलर लाईट प्लेट की गांवों के अंदर क्या जरूरत है । यह सोलर लाईट प्लेट के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं उस पैसे को उद्योग पर आप अटैच कर देते, उस पैसे को उद्योग पर लगाते तो हमाने बिहार के अंदर उद्योग होता । यह सोलर लाईट प्लेट की स्कीम जो है वह पंचायतों को आपने दे दी लेकिन पंचायतों को निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया । वह निर्णय होगा बियाडा और कौन लगाएगी यह सब लोग कुछ दिनों के बाद जानेंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जो बजट है वह काँट्राडिक्टिक बजट है । यह तय होना चाहिए कि बिहार जो शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से आज छटपटा रहा है । सरकार ने एक सार्थक कदम उठाया है शिक्षा में बजट की बढ़ात्तरी की है मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन जितनी जरूरत हो बजट का 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए । युवाओं को रोजगार के सवाल पर बजट की खामोशी ने बिहार के नौजवानों में नाउम्मीद पैदा की है । आपको पीठ जितनी थपथपानी है थपथपा लो लेकिन आपका बजट पढ़कर बिहार का एक भी नौजवान आपके पक्ष में कोई पॉजीटिव प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप सब विधायक यहां बैठे हुए हैं ये चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण कार्य विभाग की । सब विधायकों के बोर्ड लगते हैं, प्लेट लगते हैं रोडों पर । ग्रामीण कार्य विभाग अगर नहीं हो तो विधायक का नामोनिशान मिट जाएगा गांवों के अंदर सड़कों पर । 1 लाख 25 किलोमीटर सड़कें मेंटिनेंश के लिए हैं, 60 हजार किलोमीटर सड़कें पंचवर्षीय प्लान से पार कर चुकी हैं । माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं विचार करने की जरूरत है । 2 हजार करोड़ रुपया मेंटिनेंस का ऐम इन लोगों ने दिया है और 2 हजार करोड़ रुपया में जो 60 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता । आप विकास की बात कर रहे हैं ग्रामीण कार्य विभाग पास पैसे नहीं होंगे तो गांव की सड़कें नहीं बनेंगी और

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट असंतुलित है, यह बजट अपने-आप में अंतर्विरोधी है और इसलिए इसको सुधारने की जरूरत है । जहां तक कृषि की चर्चा चल रही है । बिहार सरकार कृषि के डेवलपमेंट के लिए जोर-जोर से ताली पीट रही है, बिहार के किसानों की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, चले जाइये गंगा के उस पार जिले के एक-तिहाई हिस्से में जल-जमाव की समस्या है । जल-जमाव का निस्तारण करने के लिए योजना होनी चाहिए, वह योजना नहीं है । हम कई वर्षों से लगे हैं, हमसे पहले के विधायक भी और उनसे पहले के भी विधायक छटपटाते रहे जब सारण जिले के अंदर सारण प्रमंडल के अंदर जो जल-जमाव की समस्या है उसके निदान के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए लेकिन बजट के संतुलित खर्च के चलते गंगा के उस पार के इलाकों को हम जल-जमाव से मुक्ति नहीं दिला सके । उसको जल-जमाव से मुक्ति देते, उस पर बजट खर्च करते तो खेती में उन्नति आती, खेती में पैदावार बढ़ती लेकिन आपकी प्राथमिकता में वह नही है और जिसके चलते कृषि डेवलप नहीं हो रही है । आप कह रहे हैं कृषि विकास और किसानों के लिए बहुत-सी योजनाएं चल रही हैं दलाल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दलाल लूट रहे हैं किसानों को फायदा नहीं हो रहा है । कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भूमि सुधार के साथ जल-जमाव की समस्या का निदान होना चाहिए और हर...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

हर किसान के खेत तक पानी के लिए जल संसाधन विभाग की जो भी योजनाएं चल रही हैं वे कागज पर हैं, उस पैसे का भ्रष्टाचार में इस्तेमाल होता है । बिहार को विकसित बिहार बनाना है तो कृषि, रोजगार और शिक्षा पर आपको फोकस करना चाहिए । आपने कहा सामाजिक क्षेत्रों में बड़ा पैसा खर्च किया है । आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आप पैसा खर्च करते हैं, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो पैसा आप देते हैं वह क्या वास्तव में बच्चों को मिलता है । वह पैसा आपके अधिकारी गटक जाते हैं आप सामाजिक क्षेत्रों में और चर्चा करते हैं स्किल डेवलपमेंट करिये, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो पैसे जाते हैं इसलिए...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव : मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का जो बजट है वह असंतुलित है और इस बजट से बिहार का विकास नहीं होगा । बेईमान, भ्रष्ट लोगों और ठेकेदारों के हाथ में इस बजट की बड़ी राशि जाएगी इसलिए सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और उद्योग विभाग के बजट में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में भी बढ़ोत्तरी करके सड़कों का निर्माण कराना चाहिए और स्ट्रीट

लाईट, मैं सख्त एतराज जताना चाहता हूं आपने स्ट्रीट लाईट का प्रोग्राम दिया है और आप कहते हैं कि आप 24 घंटे बिजली देते हैं तो...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये । माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार साहनी जी ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव : अपनी बात पर कायम रहिये । जब 24 घंटे बिजली देते हैं तो स्ट्रीट लाईट की कोई जरूरत नहीं है यह अगर आपने शुरू किया है तो बड़ी कंपनियों को ठेका देने के लिए किया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बजट को संतुलित कीजिये और जो बजट इधर-उधर खर्च कर रहे हैं उस बजट को जोड़कर उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाइये जिससे...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव : बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल सके । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अनिल कुमार साहनी : अध्यक्ष महोदय, यह बजट जो लाया गया है और हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो रखा गया है वह बजट सरासर गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, अतिपिछड़ा विरोधी है, मछुआ विरोधी है यह बजट । मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यह जो गीत गा रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न-23/मुकुल/03.03.2022

...क्रमशः...

श्री अनिल कुमार साहनी : माननीय वित्त मंत्री जी ये गीत पुराना गाते हैं, बिहार के गरीबों और नौजवानों को भरमाते हैं और दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं । जिस प्रकार से इस बजट को लाया गया है, इसमें बताया गया है कि कृषि पर 29 हजार करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो आप 29 हजार करोड़ रुपया कहां खर्च करेंगे । कृषि के जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अगर 29 हजार करोड़ रुपये में से किसानों के पास 5 परसेंट भी पैसा नहीं पहुंचता है, आपके कमीशन में वह पैसा चला जाता है । आप कहते हैं कि 29 हजार करोड़ रुपये देंगे, किसान और मजदूर आज किस प्रकार से इस कोरोनाकाल में और आये हुए बाढ़ में किस प्रकार से किसान और मजदूरों का हाल रहा, आपने अभी तक कृषि इनपुट का पैसा नहीं दिया । आपने कहा कि कृषि इनपुट के द्वारा हम किसान को पैसा देंगे, आज तक हमारे कुढ़नी विधान सभा क्षेत्र में किसी भी किसान को सही रूप से नहीं मिला है और आप कहते हैं कि कृषि के लिए नया बजट लाये हैं, वही गीत पुराना गाते हैं और आपने कहा कि शिक्षा पर 39 हजार करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो आप 39 हजार करोड़ रुपया कहां पर खर्चा करने जा रहे हैं । अभी तक हमारे ही क्षेत्र में कई जगह देखिए बड़े-बड़े

बिल्डिंग बन गये, मगर बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, क्या आप उसपर खर्चा करने जा रहे हैं या इसमें भी बंदरबांट करने जा रहे हैं । यह बजट जो दिखाई दे रहा है, बिहार की जनता को सरासर धोखा देने वाला बजट दिखाई पड़ रहा है और इसके माध्यम से सिर्फ लूट किया जायेगा । आपने जल-नल, मैं तो कहता हूं जल-नल छल है, बहुत बड़ा छल है । माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर गये थे, मैंने समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी संयोग से आप आज हेलीकॉप्टर से नहीं आये हैं, आप बाई कार से आये हैं और कार से आप जाइयेगा तो हमारे ही विधान सभा क्षेत्र से जिसमें 8-9 पंचायत पड़ेगा, रामदयालु से लेकर फकुली तक । माननीय मुख्यमंत्री जी आप किसी भी पंचायत में जाकर देख लीजिए कि जल-नल का क्या हाल है । बजट आप दे रहे हैं तो जल-नल का मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस करने के लिए आप पैसा दीजिए । हमलोग जो विधायक हैं जहां भी जाते हैं, यहां पर हमारे सत्तापक्ष और विपक्ष के भी विधायक बैठे हुए हैं, आपलोग भी दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आपकी जनता कहती है कि नहीं कि जल-नल फेल हो गया है, हमें चापाकल चाहिए, बोलता है कि नहीं कि हमें चापाकल चाहिए तो आप जल-नल के नाम पर बिहार को छलने का काम किये हैं, आप छलिया हैं, आप इस बिहार की गरीब जनता को, शोषित/उपेक्षितों को जिस प्रकार से आपने ठगने का काम किया है यह जनता माफ करने वाली नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर हम 16 हजार करोड़ रुपया देंगे, कहीं पर दवाई नहीं, कहीं पर खटाई नहीं और कहीं पर बेड नहीं । हमारा जो पारस हॉस्पिटल में लूट हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है । अगर कोई व्यक्ति संयोग से अपनी जान बचाने के लिए उसमें चला गया तो 10-20 लाख रुपया दे देता है उसके बाद जब कहा जाता है कि अब पेसेंट को दूसरी जगह ले जाइये तो मरीज के परिजन विधायकों के पास, आपलोगों के पास भी जाते होंगे और कहते होंगे कि यहां से पी0एम0सी0एच0 में भिजवा दीजिए, इंदिरा गांधी में भिजवा दीजिए या एम्स में भिजवा दीजिए, पैसा जब खत्म हो जाता है, जब पारस में वह पैसा से लूटा जाता है तो इसको भी देखने वाला कोई नहीं है । इस बजट में जांच भी करने की प्रक्रिया रखिए कि आपका कितना-कितना पैसा लूटा जा रहा है । वहीं पर आपने जो मत्स्य और पशु पालन, आज मछुआरा समाज के लाखों, निषाद समाज के, मल्लाह समाज के जिनका जलकर से जीवन चलता है और उनको कहीं-कहीं, जल-जीवन-हरियाली में उनको जो है, मिट्टी भरा जा रहा है । आज लाखों मछुआरे, लाखों मल्लाह/निषाद के लोग, जिनका परम्परागत मछली पालन करने का और मछली पर आधारित रहने का जो काम था, आज उसपर रोक

लगता जा रहा है, आप उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किये हैं कि इनका जो रोजी-रोटी परम्परा है वह कहां जा रहा है । वहीं पासी भाइयों के लिए आपने किसी प्रकार का इसमें प्रावधान नहीं किया, जो परम्परागत पासी भाई थे जो पेड़ पर चढ़कर ताड़ी उतारते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नीरा का उत्पादन कीजिए तो नीरा का उत्पादन करने के लिए आपने कोई बजट नहीं दिया । आप उन पासी समाज के लोगों से ताड़ी को खरीद लीजिए और उसका नीरा बनाइये और मार्केट में बेचिए । आज पासी समाज जो 20 फीट/50 फीट ऊपर जाकर ताड़ उतारता है और नीचे में जो मल्लाह मछली निकालता है, आज मल्लाह और पासी का जो समीकरण था इस कारण से खत्म होता जा रहा है और वे पकड़ा-पकड़ा कर जेल में जा रहे हैं । माननीय वित्त मंत्री जी आपने प्रावधान नहीं किया कि पासी समाजों का, आप जो नीरा बनाइयेगा उसके लिए फैक्ट्री कहां-कहां खोल रहे हैं, उसमें आप नीरा बनाने के लिए कितना करोड़ रुपया दे रहे हैं, नीरा बनाने वाले लोगों के लिए, पासी समाज के लिए, नीरा उद्योग खोलने के लिए, जो परम्परागत काम करते थे पेड़ पर से वह उतारे और आप उसी जगह उनसे खरीद लीजिए, आप उनसे खरीद लीजिए । मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आप इन गरीब और गुरबों को जो सताने का काम कर रहे हैं, आप उनके पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं तो यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है । जो बजट प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2022-23 पर 2 लाख 37 हजार 691 रुपया का जो आपने पेश किया है, यह लगता है कि सिर्फ बंदरबांट करने के लिए पेश किया गया है और इससे किसी आने वाले बिहार के लोगों को, जैसे आप इस 15 सालों से जो बजट पास कर रहे हैं, कहीं पर आपका दिखाई नहीं पड़ता है, किसी भी गरीब के घर में, झोपड़ी वाले के घर में, इस बजट के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है, यह हमलोग अपने क्षेत्र में ही देखते हैं ।

(व्यवधान)

सुनिये, अब सही बात बोलेंगे तो लगेगा ही । 'सत्य कहे सो मारा जाय और झूठा जग पतिआये' और बिहार के लोग होशियार हो गये हैं आपके इस बहकाने वाले कार्य में पड़ने वाले नहीं हैं और आप इस बजट के माध्यम से जिस प्रकार से ठगने का काम कर रहे हैं, वे ठगाने वाले नहीं हैं । झूठ बोलकर और झूठ का काम करके आप गरीबों को बहकाने वाले नहीं हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह प्रावधान करवाइये कि....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री अनिल कुमार साहनी : आपलोगों को बोलना चाहिए ।

''सत्य कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं ।''

आपमें सत्य कहने का हिम्मत नहीं है, सत्य सुनने का भी हिम्मत नहीं है, आप सत्य की ओर जाने वाले नहीं हैं । आप जिस प्रकार से इस बजट को बनाये हैं वह गरीब विरोधी है, मजलूम विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और बेरोजगारी से जो मर रहा है ।

अध्यक्ष : क्या इनका समय और बढ़ा दिया जाय ?

श्री अनिल कुमार साहनी : अध्यक्ष महोदय, नहीं ।

अध्यक्ष : आप लोग बताइये कि क्या इनका समय बढ़ा दें ।

श्री अनिल कुमार साहनी : अध्यक्ष महोदय, 19 लाख रोजगार पर कुछ नहीं बोले, उसमें कितना बजट दे रहे हैं, 19 लाख बेरोजगार लोग जो मर रहे हैं । आज जब वे सड़कों पर, राज्यपाल जी के यहां, मुख्यमंत्री जी के यहां धरना देने जाते हैं तो लाठी से पीटकर भगाया जाता है, सरकार को उसपर भी कुछ बजट रखना चाहिए था कि गरीब/नौजवान जो रोड पर भुखमरी का शिकार हो गये हैं । मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको सुझाव देता हूं कि गरीब/नौजवान/बेरोजगारों के प्रति भी आप इस पर विचार कीजिए और उनको 19 लाख नौकरी दीजिए ।

अध्यक्ष : बजट पर सामान्य विमर्श कल भी जारी रहेगा ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 03 मार्च, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-40 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।